04 - पड़ोसी देशों में अराजकता और भारतीय संविधान की ताकत

05 - क्या नई पीढ़ी बालेन शाह जैसे चेहरों के साथ जातीय ढांचे को बदल पाएगी?

A Daily News Magazine

भोपाल

शनिवार, 13 सितंबर, 2025

06 - राजस्व वसूली में गिरावट पर सीएमओ सख्त निरीक्षकों को वसूली...

07 - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हेलमेट पहन कर विद्यार्थियों को दिया...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 16, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

एआई के बूते खड़ा हो रहा फार्मा रिसर्च का नया पावरहाउस

चंद्र भूषण

भारत को अब तक जेनरिक दवाओं का हब माना जाता था, लेकिन चीन एआई आधारित दवा खोज में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जानें कैसे दुनिया में फार्मा इंडस्ट्री का समीकरण बदलने जा रहा है। इलाज के मामले में ही नहीं, दवाएं बनाने में भी दुनिया भारत की कद्र करती है, लेकिन इस बात के संदर्भ स्पष्ट होने चाहिए। सीधे 'मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री का पावरहाउस' बोल देने से गलतफहमी की गुंजाइश रह जाती है। भारत के डॉक्टरों की दुनिया में अच्छी ख्याति रही है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल चेन्स की बढ़ती मेहरबानियों के बावजूद विकसित देशों की तुलना में इलाज यहां आज भी सस्ता पड़ता है। इस क्षेत्र में भारत की एक प्रसिद्धि दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी है लेकिन इसकी चर्चा प्रायः मरीजों की लाचारी से जुड़कर होती है।

रही बात फार्मा इंडस्ट्री की तो भारत की स्थिति सिर्फ जेनरिक दवाओं के मामले में बेहतर मानी जाती है। जेनरिक दवा, यानी पश्चिम में काफी पहले खोज ली गई जिन दवाओं के पेटेंट खत्म हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा फॉर्म्यूला बदलकर या साथ में कोई और चीज फेंटकर बना दी गई दवा, जो स्वभावतः सस्ती पड़ती है। ध्यान रहे, दवाओं की कीमत में सबसे ज्यादा हिस्सा उनकी खोज और क्लिनिकल ट्रायल पर आई लागत का होता है और कंपनियां कुछ समय तक मनॉपली प्रॉफिट (अकेले विक्रेता का मुनाफा) कमा लेने के बाद ही किसी और को उसे बनाने की इजाजत देती हैं।

जड़ से नई दवाएं बनाकर बाजार में लाने का श्रेय काफी लंबे समय से मुख्यतः तीन ही देशों को जाता रहा है- अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। जाहिर है, दवा उद्योग का मुनाफा भी सबसे ज्यादा इन्हीं के हिस्से आता है। लेकिन नई दवाएं खोजने और जेनरिक दवाएं बनाने के अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक तीसरा दायरा भी है।

1980 से एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में चीन का उभार शुरू हुआ तो कुछ जोर उसने केमिकल इंडस्ट्री में भी लगाया। नई दवाओं की खोज करना उसके एजेंडा पर नहीं था। बस दवाएं बनाने में काम आने वाले रसायन सस्ते से सस्ते में बना कर थोक में बेचने का तरीका उसने खोज निकाला। नतीजा यह कि भारत समेत दुनिया भर की दवा कंपनियां सामान्य दवाओं के केमिकल उससे टनों में खरीदकर मिलीग्राम्स में पैकेजिंग-ब्रांडिंग-मार्केटिंग कर रही हैं।

यह किस्सा पिछले चार-पांच वर्षों में ही बड़ी तेजी से बदलने लगा है। विज्ञान और तकनीकी के मामलों में बदलाव इतने चमत्कारिक ढंग से होते नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ ऐसा हो गया है कि दवा उद्योग में 'डाउन द लाइन' समझे जाने वाले चीन की गिनती अचानक 'टॉप ऑफ द लाइन' मुल्कों में होने लगी है। मतलब यह कि थोक भाव में दवाओं के केमिकल बनाने वाले इस देश की पहचान अचानक बिल्कुल नई दवाएं बनाने वाले देश के रूप में बनने लगी है। यह भी कमाल की बात है कि ऐसा होने में मुख्य भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बताई जा रही है, जो अमेरिका की एक अद्यतन खोज है। इस बदलाव की तह में जाने से पहले एक नजर इसे बयान करने वाले तथ्यों पर।

नई दवाओं की खोज के मामले में 2019 तक चीन की स्थिति विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी हैसियत को देखते हुए काफी नीचे थी। फार्मा इंडस्ट्री में दुनिया के कुल 'इनोवेशन पाइपलाइन असेट्स' (दवाओं की खोज में लगे हुए संसाधन) का 10 प्रतिशत ही उसके पास था। छह साल भी नहीं गुजरे और अभी यह सीधे बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। एक नीति के तहत अपनी रिसर्च लैब्स द्वारा खोजी गई 'संभावित दवाओं' और प्रक्रियाओं (प्लेटफॉर्म्स) का लाइसेंस चीन ने विदेशी दवा कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। बायोटेक लाइसेंसिंग के इस धंधे में चीन का हिस्सा 2023-24 में पूरी दुनिया का 21 प्रतिशत था, जो 2025 में छलांग लगाकर 32 प्रतिशत हो गया है।

एस्ट्राजेनेका, फाइजर और सनोफी जैसी बड़ी दवा कंपनियों ने अभी हाल में सीएसपीसी, एक्सटालपी और हेलिक्सॉन जैसे बिल्कुल नए-नए चीनी स्टार्ट-अप्स से अरबों डॉलर के लाइसेंस खरीदे हैं।

कहीं किसी कैंसर-रोधी दवा के लिए, कहीं गठिया जैसी किसी ऑटोइम्यून डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। खुद चीनी इन दवाओं के कारोबार में जाकर सैकड़ों अरब डॉलर की सालाना कमाई कर सकते थे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रायल और नाकामी का सारा जोखिम वे अभी इन ऊंची दुकानों पर ही छोड़ दे रहे हैं। अपने प्रयोगों के लिए उनके पास 60 करोड़ स्वास्थ्य बीमा धारकों का लंबा-चौड़ा बेस है, जिन पर क्लिनिकल ट्रायल का डेटा एक समानांतर दुनिया का दरवाजा उनके लिए खोले हुए है।

कृत्रिम बुद्धि संबंधी अपने लेखों में यह बात मैं दोहराता रहा हूं कि पैटर्न पकड़ना ही एआई की बुनियाद है। बड़े डेटासेट पर काम करने वाले बायोमेडिकल एआई मॉडल ऐसे आंकड़ों से भी बड़े-बड़े मायने निकाल लेते हैं, जिन्हें हम अपने रेग्युलर हेल्थ चेक-अप में फालतू मानकर इधर-उधर फेंक देते हैं। मसलन, एक हीमोग्राम में बीसेक संख्याएं निकलकर आती हैं। उनमें कोई आंकड़ा बोल्ड हुआ तो लोगों का ध्यान उसपर जाता है। डॉक्टर के लिए भी मायने उसी के होते हैं। लेकिन अगर मशीन लर्निंग से किसी खास कैंसर के 1000 मरीजों में इन डेटा का कोई पैटर्न बिना किसी बड़े बदलाव के भी खोजा जा सके तो उस कैंसर का रुझान बायोप्सी से पहले ही पकड़ा जा सकता है। फार्मा रिसर्च में सक्रिय चीन के एआई बेस्ड स्टार्ट-अप बीमारियों और दवाओं के रिश्ते इसी तरह खोज रहे हैं।

हमारे देश में योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग नाम की एक संस्था कायम की जा चुकी है, लेकिन चीन में योजना आयोग आज भी न केवल बचा हुआ है बल्कि पंचवर्षीय योजनाएं आज भी उसके विकास की धुरी हैं। 2025 से 2030 के लिए पेश की गई पंचवर्षीय योजना में सरकारी फंडिंग और सपोर्ट के लिहाज से 'एआई ड्रग डिस्कवरी' को प्राथमिकता दी गई है। टेंसेंट, बाइदू, बाइटडांस और अलीबाबा जैसी चीन की ताकतवर टेक-कंपनियां भी हेल्थ डेटासेट्स के खजाने और अपनी वैज्ञानिक जनशक्ति का महत्व अच्छी तरह जानती हैं।

यही वजह है कि वे दवाओं के क्षेत्र में उभर रही रिसर्च कंपनियों को फाइनेंस कर रही हैं या अपनी तरफ से ही ऐसी कंपनियां शुरू भी कर रही हैं। इस पंचवर्षीय योजना में मिलने वाला तगड़ा सरकारी समर्थन 2030 आते-आते ऐसी स्टार्ट-अप कंपनियों को दवाओं से जुड़े शोध की महाशक्ति बना सकता है। अमेरिकी, फ्रांसीसी और स्विस फार्मा कंपनियों के लिए अभी इनसे लाइसेंस खरीदना फायदे का सौदा जरूर है लेकिन आगे यही उन्हें हौआ लगने लगेंगी।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

आँख भर आई किसी से
जो मुलाक़ात हुई
ख़ुश्क मौसम था मगर
टूट के बरसात हुई
दिन भी डूबा कि नहीं
ये मुझे मालूम नहीं
जिस जगह बुझ गए
आँखों के दिए रात हुई
कोई हसरत कोई
अरमाँ कोई ख्वाहिश ही न थी
ऐसे आलम में मिरी ख़ुद
से मुलाक़ात हुई
इसी होनी को तो
क़िस्मत का लिखा कहते हैं
जीतने का जहाँ मौक़ा
था वहीं मात हुई
इस तरह गुज़रा है
बचपन कि खिलौने न मिले
और जवानी में बुढ़ापे से
मुलाक़ात हुई।

- मंज़र भोपाली

दुनिया के लोगों को डर लग रहा है कि भारत बड़ा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा

कुछ लोग सोचते हैं वह भारत पर दबाव बना लेंगे

नागपुर (एजेंसी)। टैरिफ और रूस से तेल आयात के चलते भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है, जिसके चलते दुनियाभर में उनकी किरकिरी हो रही है। इस बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका का बिना नाम लिए हुए टैरिफ को लेकर उनपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में लोगों को डर लगता है कि ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां होगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं। जिसने किया था, उसको पुचकार रहे हैं, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। यह क्यों है, सात समंदर पार आप लोग हैं, हम यहां पर हैं। कोई संबंध तो है नहीं, लेकिन डर लगता है।

अगर मनुष्य अपना रवैया बदल ले सब ठीक हो जाएगा

भागवत ने कहा कि भारत महान है और भारतीयों को भी महान बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत बड़ा है तथा वह और बड़ा होना चाहता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अगर मनुष्य अपना रवैया ''मैं'' से ''हम'' में बदल लें तो सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे। दुनिया समाधान तलाश रही है। भागवत ने कहा कि मनुष्य और राष्ट्र जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक वे समस्याओं का सामना करते रहेंगे। नागपुर में ब्रह्माकुमारी विश्व शांति सरोवर के सातवें स्थापना दिवस समारोह में भागवत ने कहा कि ब्रह्माकुमारी की तरह ही आरएसएस भी आंतरिक चेतना को जागृत करने के लिए काम करता है।

सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति

इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी कार्यक्रम में नजर आए।

सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम बनी

- ली शपथ, काठमांडू के मेयर का मिला समर्थन

नेपाल में भारतीय पत्रकारों के साथ हुई मारपीट

काठमांडू (एजेंसी)। सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात 9.30 बजे नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की। उनके नाम पर फाइनल सहमति बनी । नेपाल के राष्ट्रपति संसद भंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। काठमांडू मेयर बालेन शाह और उनके समर्थकों ने सुशीला का समर्थन किया है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। दूसरी तरफ नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट और बदसलूकी की कई घटनाएं सामने आई हैं। शुक्रवार को भी दो भारतीय पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने उनका समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। उन्होंने 1979 में वकालत में अपना करियर शुरू किया था।

नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंचा

नेपाल में हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई है। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। काठमांडू में हालात सामान्य होने लगे हैं। सेना गश्त कर रही है, दुकानें खुलीं और मलबा साफ किया जा रहा है। भारत ने विशेष उड़ानों से नागरिकों को निकालना शुरू किया; आंध्र प्रदेश के 140 लोग सुरक्षित लौटे। कई भारतीय सोनौली और पानीटंकी जैसे बॉर्डर से भी वापस आ रहे हैं। दिल्ली-काठमांडू बस नेपाल में फंसी है, वहीं अयोध्या के 8 यात्री हिलसा में अटके हैं। भारतीय वॉलीबॉल टीम को भारतीय दूतावास ने बचाया; मेंबर उपासना गिल की वीडियो अपील वायरल हुई थी।

लाड़ली बहनों के खातों में आए 1541 करोड़ रुपए

बहनों की खुशहाली ही सरकार का मिशन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की सभी बहनों के जीवन में नित नई मुस्कान लाना सरकार का संकल्प है। बहनों की खुशहाली ही हमारा मिशन है। राज्य सरकार बहनों को आत्मनिर्भर बनाने देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन, लाड़ली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं के जरिए कदम-दर-कदम आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील सरकार है। हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है। प्रदेश की बहनों को हर महीने प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बहनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बहनों के जीवन में विकास से ही पूरे समाज का विकास संभव है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 28वीं किश्त की 1541 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने 53.48 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी 320.89 करोड़ राशि और 31 लाख से अधिक बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग के 48 करोड़ रुपए अंतरित किये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी अनेक सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पेटलावद में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड, श्रृंगेश्वर तीर्थस्थल में घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, राजगढ़-पारा-राणापुर-पिटोल मार्ग 55 किमी 2 लेन मार्ग निर्माण, एनएच-47 दत्तीगाँव फाटे से उमरकोट-बोलासा रायपुरिया 2 लेन मार्ग निर्माण 30.80 किमी, एनएच-47 से माछलिया मृगारुंडी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल एवं मार्ग, झाबुआ-कल्याणपुरा-रायपुरिया मार्ग पर ग्राम कदवाली में टूटी पुलिया का निर्माण, ग्राम धतुरिया जिला झाबुआ से माही नदी पर पुलिया एवं लाबरिया जिला धार तक मार्ग निर्माण और ग्राम पारा विकासखंड रामा में नवीन नलजल योजना के निर्माण की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झाबुआ जिले में 25 करोड़ की लागत से विभिन्न छात्रावास बनाए जाएंगे। झाबुआ के जनजातीय बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनें और राज्य सरकार उनके देश से लेकर विदेश तक पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहुत जल्द मैं झाबुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने आऊंगा।

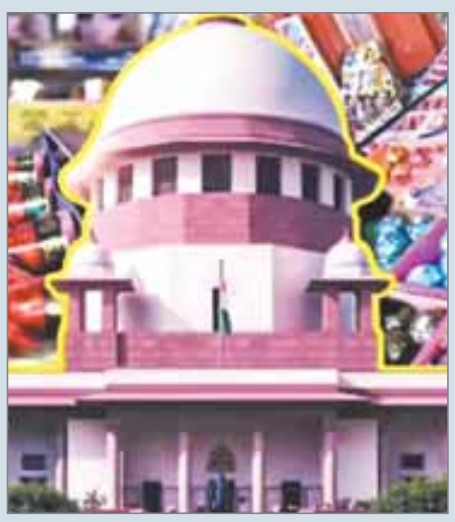

दिल्ली-एनसीआर ही क्यों, देशभर में बैन हों पटाखे

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पूरे देश को साफ हवा का हक - सख्त राय, दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अगर दिल्ली-एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में बैन करना चाहिए। साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी जो भी नीति हो वह पूरे भारत में होनी चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए इसलिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि यहां देश के एलीट वर्ग हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है। सीनियर एडवोकेट बोलीं- अमीर लोग प्रदूषण होने पर दिल्ली से चले जाते हैं। सुनवाई के दौरान अपराजिता सिंह ने राय रखी।

एससी के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी-रील बनाने पर बैन

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए मुख्य परिसर में फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर बैन लगा दिया है। 10 सितंबर को जारी सर्कुलर में कोर्ट ने मीडियाकर्मियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इस सर्कुलर के मुताबिक कम सुरक्षा वाले लॉन एरिया में ही इंटरव्यू और लाइव टेलीकास्ट कर सकेंगे। अगर मीडियाकर्मी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी एरिया में उनकी एंट्री एक महीने के लिए बैन की जा सकती है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 30 °c

न्यूनतम 25°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 13 सितंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

बिना सर्वे फसल मुआवजे की मांग

रतलाम में किसानों ने रैली निकाली, कहा- फसल पूरी तरह तबाह,11 हजार रुपए प्रति बीघा मिले

रतलाम (नप्र)। रतलाम में अतिवृष्टि से खराब फसलों का 11 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने फसल खराब होने पर बिना सर्वे के मुआवजा दिए जाने की मांग की। करनी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर सहित कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या किसान शामिल हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली। जय जवान, जय किसान के नारों के साथ हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। खराब फसलों के साथ किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां नीचे सभी नीचे जमीन पर बैठ गए। किसानों ने संबोधित कर पटवारियों द्वारा सही आकलन नहीं करने का आरोप लगाया।

70 प्रतिशत सर्वे की बात पर नाराजगी

किसानों ने मांग की पटवारी केवल 70 प्रतिशत खराब फसल का सर्वे कर रहे है। जब फसल पूरी खराब है तो 70 प्रतिशत का सर्वे क्यों किया जा रहा है। करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि अभी हम शांति पूर्ण ज्ञापन देने आए है। किसानों की मांगे नहीं मानी तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एसडीएम आर्ची हरित को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया।इस दौरान तहसीलदार ऋषभ ठाकुर समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

बिना सर्वे के दे मुआवजा

किसानों ने मांग रखी कि प्रदेश के कई इलाके में अतिवृष्टि हुई। जिसमें रतलाम जिला भी प्रभावित हुआ है। एक किसान जो पूर्ण रूप से अपने किसानी कार्य पर निर्भर है। ऐसे में अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा एवं पीले मौजेक जैसी गंभीर बीमारी को लेकर हताशा से भरा हुआ है। संज्ञान में लेकर बिना सर्वे के किसानों को सहायता प्रदान की जाना चाहिए। जिससे किसान को शासन स्तर से राहत मिल सके।

किसान बोले- फसलें पूरी बर्बाद, सीधे मुआवजा मिले

किसानों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वे में समय व्यर्थ न करते हुए किसानों को राहत देने के लिए तुरंत एक निश्चित राशि तय कर सीधे उनके खातों में जमा की जाए। बीमा कंपनियां बार-बार पॉलिसी नंबर मांगकर किसानों को परेशान करती हैं। बैंक और बीमा कार्यालयों में घंटों समय बर्बाद होता है, किसान साथी परेशान होता है लेकिन समाधान नहीं है।

सिक्किम में लैंडस्लाइड चार लोगों की मौत

- आगरा में 40 गांव डूबे, हिमाचल में बाढ़-बारिश से अब तक 380 की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। वेस्ट सिक्किम के यांगथांग के अपर रिंबी इलाके में शुक्रवार रात लैंडस्लाइड हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग लापता हैं। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेज धार नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी चल रहा है। यूपी के आगरा में यमुना में बाढ़ है। यहां 25 कॉलोनियां और 40 गांव में 2-5 फीट

तक बाढ़ का पानी भरा है। ताजमहल के पीछे बना पार्क पूरी तरह से डूब गया। 5 हजार से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश-बाढ़ के कारण 380 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लापता हैं। सबसे ज्यादा 48 मौतें लैंडस्लाइड में गई। बादल फटने से 17 की मौत हुई है। आज 3 नेशनल हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा के जलस्तर ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।

पीएम के सपने में आई मां, बोलीं-राजनीति के लिए कितना गिरोगे

- बिहार कांग्रेस का एआई वीडियो पोस्ट, गिरिराज ने कहा-राहुल गांधी की मां नकली, गिर गए हैं

पटना (एजेंसी)। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने पर मचे बवाल के बाद बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट

किया है। इस वीडियो के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। 36 सेकेंड के एआई जेनेरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है- साहब के सपनों में आईं मां। देखिए रोचक संवाद। गुरुवार रात शेयर हुए इस वीडियो में दिखाया गया है, प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर कह रही है कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे।

जमानत पर बाहर रहने वाले सत्ता का देख रहे सपना

- पटना में अनुराग ठाकुर का तेजस्वी यादव पर सख्त तंज

पटना (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को पटना पहुंचे हैं। जिस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां का वर्चुअल

वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने पर कहा कि राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है यह राजद और कांग्रेस ने बता दिया। प्रधानमंत्री की मां का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और उस संवेदनशील अवधि के दौरान इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाना निंदनीय है। मां को गाली देने वालों का रिश्ता राजद और कांग्रेस से ही हो सकता है।

मंजूर नहीं पुरानी रिपोर्ट, नई जातीय गणना के आदेश

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का महीने भर में तीसरा दांव

बेंगलुरु (एजेंसी)। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य में 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच दशहरा की छुट्टियों के दौरान एक नया सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2015 में की गई जाति जनगणना को सरकार ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली जनगणना के आंकड़े एक दशक पुराने हो चुके हैं, इसलिए समाज की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए नई जाति जनगणना जरूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, समाज

में कई धर्म और जातियां हैं। विविधता और असमानता भी है। संविधान कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार होने चाहिए और सामाजिक न्याय होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नया सर्वेक्षण असमानताओं को दूर करने और लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। **2 करोड़ परिवारों को किया जाएगा शामिल-** कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए जाने वाले इस सर्वे में राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों के तहत आने वाली करीब 7 करोड़ पूरी आबादी को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस सर्वे के दौरान विशिष्ट पहचान पत्र मिलेगा।

- बिजली मीटर के नंबरों की होगी जियो-टैगिंग

रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे के दौरान हरेक घर को बिजली मीटर के नंबरों से जियो-टैग किया जाएगा, और मोबाइ नंबों को राशन कार्ड और आधार से जोड़े जाएँगे। जो लोग सर्वे कर्मियों को अपनी जाति का विवरण नहीं देना चाहते, उनके लिए एक समर्पित हेल्पलाइन (8050770004) पर कॉल करके या ऑनलाइन जानकारी देने के विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नागरिकों से पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया। मधुसूदन नाइक की अध्यक्षता वाले आयोग को वैज्ञानिक और समावेशी तरीके से सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है। उम्मीद है कि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2025 तक सौंप देगा। बता दें कि इससे पहले भी सर्वे हो चुका है।

स्पाइसजेट फ्लाइट का टायर टेकऑफ के दौरान रनवे पर गिरा

- पायलट ने उड़ान जारी रखी, मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिग कराई; सभी 75 यात्री सुरक्षित

मुंबई (एजेंसी)। गुजरात के कांडला से मुंबई आ रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार को कांडला एयरपोर्ट पर टेकऑफ के दौरान बॉम्बार्डियर एस 400 प्लेन का एक टायर रनवे पर गिर गया। इसके बावजूद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उड़ान जारी रखी। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग से पहले फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालांकि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और खुद टर्मिनल तक पहुंचा। सभी 75 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। एयरलाइन ने घटना की पुष्टि की है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है और तकनीकी कारणों का पता लगाया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो के एआई 321 प्लेन की टेल (पिछला हिस्सा) रनवे से टच हो गई। एयरलाइन ने बताया कि खराब मौसम के चलते पायलट ने लैंडिंग के बजाय गो-अराउंड (दोबारा टेकऑफ की प्रक्रिया) करने का फैसला लिया। इसी दौरान विमान की टेल रनवे से टकरा गई। इंडिगो ने बयान जारी करते हुए कहा-,321 विमान ने कम ऊंचाई पर गो-अराउंड किया। इस दौरान टेल रनवे से छू गई। बाद में विमान ने दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग की। एयरलाइन ने कहा, सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। घटना के बाद विमान की जांच और मरम्मत की जाएगी और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही इसे दोबारा ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा।

कश्मीर से दिल्ली तक चलेगी 'सेब एक्सप्रेस'

घाटी के किसानों को आज से मिलेगी यह सुविधा

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादक किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। रेलवे का कहना है कि शनिवार यानी 13 सितंबर से कश्मीर से दिल्ली के लिए सेब एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन किसानों को उनकी फसल सुरक्षित और तेजी से दिल्ली पहुंचाने में मदद करेगी। भारी बारिश, भूस्खलन के चलते श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला हाईवे इस महीने बाधित रहा है। ऐसे में इस परेशानी से निपटने के लिए रेलवे ने यह तैयारी की है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच हाइवे

बंद होने से आवाजाही प्रभावित हुई है और इसके चलते कश्मीरी सेब भी दिल्ली तक नहीं आ पा रहा था। अब इस संकट से निपटने के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पीएम मोदी का मणिपुर दौरा तय, आज पहुंचेंगे इंफाल

- तीन दिवसीय दौरे में 4 राज्यों को 71,850 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

इंफाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा तय हो गया है। पीएम मोदी 13 से 15 सितंबर के बीच पूर्वोत्तर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान

वह मणिपुर भी जाएंगे। वह अपने तीन दिन के दौरे में 71,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर (शनिवार से सोमवार) तक पांच राज्यों, मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे और 71,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मिज़ोरम का दौरा करेंगे और सुबह लगभग 10 बजे आइजोल में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के बयान के अनुसार वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे।

बिना खून बहाए, भ्रष्ट शासन का नहीं होगा खात्मा

नेपाल से सीखें बंगाल के युवा,बीजेपी नेता की अपील पर विवाद

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विपक्षी भाजपा के एक नेता ने राज्य भर के युवाओं से पड़ोसी देश नेपाल में हुए जेन जेड आंदोलन से सीख लेने की अपील की है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने गुरुवार को कहा कि बिना खून बहाए, भ्रष्ट शासन का खात्मा नहीं हो सकता। उनके इस बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेता पर राज्य में हिंसा भड़काने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने राज्य भर में भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी है। नेपाल में चल रहे उठापटक और संकट पर गुरुवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, भाजपा नेता ने कहा, बंगाल के युवा राज्य की इस भ्रष्ट

सरकार से कब निपटेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। बिना खून बहाए, भ्रष्ट शासन का खात्मा नहीं होता। कई लोगों ने कहा कि (महात्मा) गांधीजी ने गीत गाकर देश को आजाद कराया। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें विश्वास नहीं करता। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा नेता आगे कहा, बेरोजगार युवाओं को नेपाल से सीख लेनी चाहिए।

जब अनपढ़ बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं: भौमिक

भाजपा नेता की इस टिप्पणी पर बैरकपुर से टीएमसी के सांसद पार्थ भौमिक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह और उनकी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राज्य भर पुलिस थानों में सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। भौमिक ने कहा, जब अनपढ़ बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं। बांग्लादेश एक देश है। नेपाल भी एक देश है। और पश्चिम बंगाल एक राज्य है। वह (सिंह) भारत के युवाओं को भारत सरकार के खिलाफ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि देश और भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार है। फिर भी, हम कभी नहीं कहेंगे कि भारत नेपाल जैसा देश है क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उन्होंने मूल रूप से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। भौमिक की टिप्पणी के बाद, भाजपा नेता ने कहा कि वह अपने खिलाफ पुलिस मामलों से नहीं डरते। सिंह ने कहा, मैं उनकी धमकियों से नहीं डरता। वे मेरे खिलाफ जितनी चाहें उतनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लेकिन, मैं अपना रुख नहीं बदलूंगा। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में, भौमिक ने बैरकपुर में सिंह को हराया था।

समंदर में नजर आया भारतीय नारी शक्ति का दम

समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण पर निकलीं तीनों सेनाओं की दस महिला अधिकारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को तीनों सेनाओं के पहले महिला जलयात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीनों

- नौ महीने में कुछ खतरनाक जल क्षेत्रों समेत 26 हजार नॉटिकल मील करेंगी यात्रा

सेनाओं की दस महिला अधिकारी अगले नौ महीने के दौरान दुनिया के कुछ खतरनाक जल क्षेत्रों समेत लगभग 26 हजार नॉटिकल मील की दूरी तय करेंगी। दस महिला अधिकारी आइएएसवी त्रिवेणी से रवाना हुई हैं। वे आइएएसवी

त्रिवेणी से रवाना हुई हैं। समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण के इस अभियान को समुद्र प्रदक्षिणा नाम दिया गया है। दुनिया में इस तरह की यह पहली त्रि-सेवा यात्रा बताई जा रही है। यह अभियान मुंबई के गेटवे आफ इंडिया से शुरू हुआ और रक्षा मंत्री ने इसे दिल्ली से वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनाथ ने अपने संबोधन में इस यात्रा को नारी शक्ति का एक प्रतीक बताया, जो तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति और एकता, आत्मनिर्भर भारत और इसके सैन्य व कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगले नौ महीनों में 26 हजार मील की यात्रा करेंगी।

बराक-8 बनेगा भारत के एयर डिफेंस का नया स्तंभ

एस-400 के साथ स्ट्रैटजिक प्लान पर बड़ा खुलासा

तेल अवीव/नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने हाल ही में एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम बनाने की अपनी रणनीतिक योजना पेश की है। इस प्लान के तहत भारत के एयर डिफेंस शील्ड में इजरायली बराक-8 डिफेंस सिस्टम को शामिल किया गया है। बराक-8 को और कई नामों से भी जाना जाता है। बराक-8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी-शिप मिसाइल और यूएवी के साथ-साथ बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जेट सहित किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत के साथ मिलकर डेवलप किया है। आपको बता दें कि साल 2017 और 2023 के बीच, यह सिस्टम इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े सौदे का

स्रोत रही। अप्रैल 2017 में भारत ने करीब 1.6 अरब डॉलर में बराक 8 सिस्टम को खरीदा था और लगभग एक महीने बाद 630 मिलियन डॉलर में बराक 8 मिसाइलों के नौसैनिक वैरिएंट को भी भारत ने खरीदा था। भारतीय युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर पर बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है।

संभागायुक्त कार्यालय में आगजनी का मामला

गंजबासौदा के रामसिंह पर केस दर्ज, कोर्ट में पेश; जेल भेजा जाएगा

भोपाल (नप्र)। संभागायुक्त कार्यालय में गुरुवार को हुई आगजनी मामले में कोहेफिजा पुलिस ने आरोपी रामसिंह अहिरवार (65) को आज कोर्ट में पेश कर दिया है। जहां से उसे जेल भेजा जाएगा। रामसिंह विदिशा जिले के गंजबासौदा तहसील के सियारी गांव का रहने वाला है। वह अपनी जमीन की फरियाद लेकर कमिश्नर ऑफिस आया था। जांच में सामने आया कि आरोपी की मां के नाम पर 2021 में मिला पट्टा निरस्त कर दिया गया था और जमीन पर रास्ता निकाल दिया गया। इसी को लेकर वह जिले में लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, लेकिन समाधान न होने पर वह संभागायुक्त से मिलने आया था। उसका तीसरा नंबर था पर वह पहले मिलने की जिद कर रहा था, जब ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में डंडा मारा और पेट्रोल छिड़ककर सोफे में आग लगाई थी। थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने वेटिंग रूम में रखे सोफों पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। इस दौरान ऑफिस में अफरा-तफरी मच गई और करीब डेढ़ घंटे तक बिजली गुल रही। घटना के वक्त संभागायुक्त संजीव सिंह भी दफ्तर में मौजूद थे। एसआई संजीव कुमार धाकड़ ने जानकारी दी कि आरोपी पर बीएनएस धारा 326 प्रतिशत के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घटना के बाद मची अफरा-तफरी

आगजनी से वेटिंग रूम धुएं से भर गया। वहां मौजूद लोग चीखते हुए बाहर भागे। ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी भी बाहर निकल आए। इसी बिल्डिंग में कृषि विभाग, जनसंपर्क और तहसील कार्यालय भी संचालित होते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई थी।

मिशन कर्मयोगी में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2.30 लाख शिक्षकों का किया पंजीयन

- पंजीकृत शिक्षकों को दक्षता के लिये दिया जायेगा प्रशिक्षण

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर पंजीकरण कर मिशन कर्मयोगी में 55 विभागों में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में 2 लाख 30 हजार शिक्षकों का igot पोर्टल पर प्रशिक्षण देने के लिये पंजीकरण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने केन्द्र सरकार के मिशन कर्मयोगी योजना में सरकारी शिक्षकों की कार्य क्षमता प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाने के लिये मुहिम शुरू की है। देश में इस कार्यक्रम की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर मिशन कर्मयोगी के नाम पर की गई है।
मिशन कर्मयोगी में यह निर्णय लिया गया है कि देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को 3 प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए, इसमें 70 प्रतिशत प्रशिक्षण डिजिटल माध्यम से दिया जायेगा। योजना में 20 प्रतिशत प्रशिक्षण ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और 10 प्रतिशत प्रशिक्षण प्रत्यक्ष मोड से होंगे।

कर्मयोगी igot पर सीखें सप्ताह

केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 15 से 19 सितम्बर 2025 तक कर्मयोगी igot पर सीखें सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान राज्य सरकार के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को न्यूनतम 2 प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यापक निर्देश जारी किये है।

राजधानी में कंडम गाड़ियों को हटाने की बड़ी कार्रवाई

कोहेफिजा इलाके में एडीएम-एसडीएम की मौजूदगी में हटाए वाहन; अतिक्रमण भी तोड़ा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में गुरुवार को सड़क किनारे खड़ी कंडम गाड़ियों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। एडीएम अंकुर मेश्राम और एसडीएम रविशंकर राय की मौजूदगी में पुलिस और नगर निगम के अमले ने कोहेफिजा इलाके में यह कार्रवाई की। एडीएम मेश्राम ने कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई जारी रहेगी।

दोपहर में अमला कोहेफिजा इलाके में पहुंचा। यहां सड़क किनारे ही कई गाड़ियां महीनों से खड़ी थी। इनमें कई कारें और टू व्हीलर्स भी शामिल थे। वहीं, अतिक्रमण भी जमा था। ऐसे में पुलिस ने पहुंचते ही गाड़ियों को हटाना शुरू किया। इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया।

100 से ज्यादा गाड़ियों को हटाया

गुरुवार को की गई कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक गाड़ियां हटाई गईं। वहीं, कई पक्के अतिक्रमण हटाए गए। एमपी नगर, कोलार समेत अन्य इलाकों में भी कार्रवाई की गई।

विवाद न हो, इसलिए पुलिस बल तैनात

अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई विवाद न हो, इसलिए पुलिस बल तैनात रहा। पूरी कार्रवाई पुलिस के साये में की गई। हालांकि, कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन अफसरों ने एक न सुनी और कार्रवाई की।

भिक्षावृत्ति करते 5 भिक्षुकों को पकड़ा आश्रम में छोड़ा

गुरुवार को ही लालघाटी चौराहे पर लंबे समय से भिक्षावृत्ति कर रहे पांच भिक्षुओं को प्रशासन की टीम ने पकड़ा और उन्हें आश्रय गृह पर भेजा। एसडीएम रविशंकर राय के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमण प्रभारी अधिकारी महेश गोहर, नायब तहसीलदार दिनकर चतुर्वेदी के साथ महिला एवं बाल विकास ब्लॉक अधिकारी अर्चना मिश्रा, नगर निगम के अधिकारी अवध नारायण मकोरिया, अनस आलम फारुकी, असद अली, फरहान अहम, मृदुल सिंह आदि मौजूद थे। दूसरी ओर, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिस धारा में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई थी, उसे 6 माह बाद फिर से रिन्युवल नहीं किया गया है। 22 फरवरी को भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान यह आदेश दिए गए थे।
इधर, भिक्षुक गृह के लिए 12 प्रस्ताव आए हैं, लेकिन जिस संस्था को काम देना है, उसका चयन जुलाई में ही हो चुका है। पहले जिस संस्था को काम दिया था, वह बिना टेंडर के दिया था। जीआईएस के चलते ऐसा हुआ था। ब्लैक लिस्टेट कंपनी को ही काम सौंप दिया

कृषि मंत्री शिवराज बोले-

सभी जिलों में खाद का पर्याप्त स्टॉक

- कलेक्टरों को व्यवस्था कराने दिए निर्देश; किसानों ने शिवराज के सामने किया था विरोध

भोपाल (नप्र)। सतना में खाद की कमी को लेकर किसानों के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रास्ता रोके जाने के बाद अब प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई है। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना ने सभी कलेक्टरों को खाद वितरण की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री कंसाना ने कहा कि प्रदेश में खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वे अपने जिलों में खाद वितरण को सुव्यवस्थित करें, ताकि किसानों को परेशानी न हो।

शिवराज बोले-

जरूरत पड़ी तो केंद्र से और खाद दिलवाऊंगा- गुरुवार को सतना दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस समय किसानों और कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने घेर लिया, जब उन्होंने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। सतना में खाद संकट की जानकारी मिलने के बाद मैंने जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के फर्टिलाइज़र विभाग से बात की है। बारिश अच्छी हुई है, इसलिए यूरिया की मांग ज्यादा है, जिसकी पूर्ति की जा रही है।

कंसाना बोले- पर्याप्त खाद

कंसाना ने बताया कि इस साल खाद की आपूर्ति पिछले साल की तुलना में अधिक है। यूरिया की पिछले साल (1 अप्रैल से 9 सितंबर 2024) तक 15.83 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हुई थी। इस साल (9 सितंबर 2025 तक) 18.34 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक रहा, जिसमें से अब तक 16.19 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है। अभी भी 2.15 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। वहीं, डीएपी + एनपीके की पिछले साल इस अवधि में 9.39 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हुई थी। इस साल 13.96 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक रहा, जिसमें से 9.71 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है। वर्तमान में 4.25 लाख मीट्रिक टन डीएपी व एनपीके खाद मौजूद है कंसाना ने बताया कि प्रदेश में रोजाना 7 से 8 रैक खाद अलग-अलग जिलों में भेजे जा रहे हैं।

भोपाल एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो महिलाओं ने चार लाख रुपए की ठगी कर ली। आधा दर्जन लोगों से गार्ड बनवाने के नाम पर रकम ऐंठी गई थी। जब नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित थाने पहुंचे और शिकायत की। आवेदन की जांच के बाद बागसेवनिया पुलिस ने गुरुवार देर रात एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी महिलाओं की अभी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। पुलिस के मुताबिक विकास नगर निवासी देवेंद्र कुमार पुत्र रमेश रघुवंशी (37) एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। वहीं आरोपी रुबीना बी भी सिक्योरिटी गार्ड है और दूसरी आरोपी रिहाना बी एम्स में हाउस कीपिंग का काम करती है। दोनों महिलाओं ने देवेंद्र कुमार की बहन समेत करीब आधा दर्जन लोगों को एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर करीब चार लाख रुपए लिए थे।

वर्दी देकर बताया जल्द होगी ज्वाइनिंग- यह रकम आरोपियों ने अपने बैंक खातों के माध्यम से ली थी। मार्च महीने में रकम लेने के बाद दोनों महिलाओं ने पीड़ितों को सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी भी दे दी थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। इससे परेशान होकर देवेंद्र समेत सभी पीड़ितों ने थाना पुलिस को लिखित में आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।

अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं

जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खुले, कोटे से 10 प्रतिशत ज्यादा बारिश, 30 जिलों में कोटा फुल

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर-जबलपुर समेत प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जरूर रह सकता है। 15-16 सितंबर से नया सिस्टम बनने के बाद फिर से पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि, जबलपुर के आसपास डिंडोरी, मंडला जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। इनसे 1096 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के 9 गेट 0.78 मीटर ऊंचाई तक खोले गए है। ऐसे में नर्मदा का जल स्तर 5 से 6 फीट बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए बरगी बांध प्रबंधन ने नर्मदा नदी के घाटों और तटीय क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। बरगी डैम के 9 गेट 0.78 मीटर ऊंचाई तक खोले गए है।

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में जितने भी सिस्टम एक्टिव है, वे प्रदेश से काफी दूर है। इस वजह से तेज बारिश होने के आसार नहीं है। 15-16 सितंबर से सिस्टम नजदीक आएंगे।

एमपी में कोटे से 4.4 इंच ज्यादा बारिश

बता दें, प्रदेश में 16 जून को मानसून ने आमद दी थी। तब से अब तक औसत 41.6 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक 34.2 इंच पानी गिरना था। इस हिसाब से 7.4 इंच पानी ज्यादा गिर चुका है। प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37 इंच है। यह कोटा पिछले सप्ताह ही पूरा हो गया है। 4.6 इंच पानी ज्यादा गिर गया है।

गुना विधायक पर ऐक्शन ले सकती है बीजेपी

पन्नालाल ने कहा था- हिंदुस्तान में भी होंगे नेपाल जैसे हालात, युवाओं को दें मिलिट्री ट्रेनिंग

भोपाल (नप्र)। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ उपजे आक्रोश के बाद हालात बिगड़ गए थे। इस बीच मध्यप्रदेश में गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान से बवाल मचा हुआ है।

गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने गुरुवार को कहा कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात अब भारत में भी हो सकते हैं। देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है। इसलिए 18 से 30 साल तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

शाक्य गुना के उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, खेल, विकास और विश्वगुरु बनने की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर होना जरूरी है।

- **नालंदा विश्वविद्यालय और सोमनाथ के उदाहरण दिए-** विधायक शाक्य ने ये भी कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में 12 हजार विद्यार्थी और 1200 शिक्षक थे, लेकिन सिर्फ 11 लोगों ने उसे जला दिया।
6 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा और कोई बचाने नहीं निकला। इसी तरह सोमनाथ मंदिर भी आग में झोंक दिया गया।

बीजेपी ले सकती है ऐक्शन

गुना विधायक के बयान पर बीजेपी कार्रवाई कर सकती है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयान से इत्तफाक नहीं रखती। ये बयान पार्टी लाइन के विपरीत है। वरिष्ठ नेतृत्व इस पर अवश्य संज्ञान लेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अत्यंत चमत्कृत लोकतंत्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित है। यह मान्यता न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हैं। इसलिए पन्नालाल जी का बयान बिल्कुल असहमति योग्य है। कलेक्टर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने को कहा शाक्य ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि उनका यह लिखित प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाए। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को बताया जाए कि युवाओं की मिलिट्री ट्रेनिंग तत्काल शुरू की जाए। जल्दी से जल्दी इसे चालू करना जरूरी है। जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) से करबद्ध निवेदन है कि श्रीमान सावधान हो जाएं। नहीं तो ये जितने स्कूटी लेकर गए हैं न यहां से, कोई इनमें दो थप्पड़ लगाएगा और स्कूटी छुड़ा ले जाएगा।

सतना-मैहर में किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया

टोकन लेकर बारी का इंतजार कर रहे 10 हजार किसान; मार्कफेड के 6 गोदाम खाली

सतना (नप्र)। सतना जिले में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मार्कफेड के डबल लॉक गोदामों से चौथे दिन भी यूरिया का वितरण नहीं हो सका, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। धान की टॉप ड्रेसिंग के लिए किसान रोजाना खाद केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन टोकन कटवाने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही।

अधिकारियों की मानें तो अब तक सतना और मैहर में 10 हजार से ज्यादा किसान यूरिया के लिए वेटिंग लिस्ट में दर्ज हो चुके हैं। इनमें मार्कफेड के सात डबल लॉक वितरण केंद्रों से 9,954 किसान, जबकि एमपी एग्रो के एक केंद्र से 256 किसान टोकन लेकर खाद का इंतजार कर रहे हैं।

सिर्फ मैहर को मिला 110 मीट्रिक टन यूरिया- गुरुवार को झुकेही रैक हेड से सिर्फ मैहर के लिए 110 एमटी यूरिया का आवंटन हुआ, जिसका वितरण शुक्रवार 12 सितंबर को टोकन धारी किसानों को किया जाएगा। अन्य सभी केंद्र देवराजनगर, अमरपाटन, सतना सिविल लाइन, शेरगंज, उचेहरा और नागौद पूरी तरह खाली हैं।

खाद की किल्लत से किसानों में नाराजगी

खाद की किल्लत के चलते किसानों में गहरी नाराजगी है। टोकन मिलने के बावजूद खाद न मिलने से खेती पर असर पड़ रहा है। किसान रोज़ाना केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) नेहा पीयूष तिवारी ने बताया फिलहाल सिर्फ मैहर भंडारण केंद्र को यूरिया मिला है, बाकी केंद्रों को उर्वरक प्राप्त होने के बाद ही वितरण शुरू किया जाएगा। शुक्रवार को केवल सोसाइटी से खाद ली जा सकती है, डबल लॉक गोदामों से वितरण नहीं होगा।

तीन दिन से खाली हैं गोदाम

मार्कफेड के अधिकतर गोदाम तीन दिन पहले ही खाली हो चुके थे, वहीं एमपी एग्रो का स्टॉक भी 9 सितंबर से खत्म है। इसके बाद जिले में उर्वरक की कोई खेप नहीं पहुंची। इस वजह से टोकन होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिससे वे धान की फसल में टॉप ड्रेसिंग नहीं कर पा रहे।

संपादकीय

अब फ्रांस में सुलगी चिंगारी

नेपाल में जेन जी के बवाल के बाद हुए तख्ता पलट के बरक्स उधर फ्रांस में भी जन असंतोष सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। हालांकि देश की मैक्रों सरकार ने जल्द ही उस पर काबू पा लिया, लेकिन इससे यह मानना कि असंतोष खत्म हो गया है, जल्दबाजी होगी। कुछ लोगों का कहना है कि नाराज लोगों द्वारा पेरिस में किए गए हिंसक प्रदर्शन का असर अब दूसरे शहरों में दिखने लगा है। क्योंकि लोगों की मांगें सरकार मानेगी, इसकी संभावना फिलहाल नहीं लगती। बीते बुधवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुधवार सुबह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर आ गए। इसके बाद उपद्रव रोकने के लिए सरकार ने 80 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच देश के गृह मंत्री ब्रूनो रेतयो ने प्रदर्शनकारियों पर विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट पार्टियों ने किया है। इस प्रदर्शन को 'ब्लॉक एवरीथिंग' नाम दिया गया। लोगों के इस विरोध प्रदर्शन के पीछे 4 वजहें बताई जा रही हैं। पहला है राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। दूसरा है बजट में कटौती। मैक्रों सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता खासकर मध्यमवर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। तीसरा है देश में बार-बार प्रधानमंत्री बदला जाना। राष्ट्रपति मैक्रों ने विगत दो साल में पांच प्रधानमंत्री बदल गए हैं। हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। चौथा कारण है, 'ब्लॉक एवरीथिंग' आंदोलन। फ्रांस के वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है ताकि देश में सबकुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं, जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, सेबास्टियन लेकोर्नू अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। एक दिन पहले फ्रांस्वा बेरो ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके अलावा फ्रांस के नागरिक यूक्रेन युद्ध में उनके देश को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस अपनी सैनिक टुकड़ियां यूक्रेन भेजेगा। यही नहीं उन्होंने पोलैंड में युद्धक विमान भेज भी दिए हैं। इससे रूस यूक्रेन युद्ध और भड़कने की संभावना है। अगर फ्रांस इस युद्ध में भाग लेता है तो देश की माली हालत और खराब होगी। यहां मैक्रों की सामने धर्म संकट यह है कि यदि रूस ने पश्चिमी देशों पर हमला किया तो फ्रांस तो क्या कोई भी देश नहीं बचेगा। ऐसे में वो चाहकर भी इस युद्ध से खुद को अलग नहीं रख सकते। क्योंकि फ्रांस नाटो का सक्रिय सदस्य है। इस बीच फ्रांस में मुसलमानों की खिलाफ नफरत और बढ़ गई है। हाल में छह मस्जिदों के प्रवेश द्वार पर सुअर के सिर काट पर फेंके गए, जिससे मुसलमानों में रोष है। एक तरफ आर्थिक बदहाली की आशंका और दूसरी तरफ देश में बढ़ती नस्ली नफरत। फ्रांसिसी राष्ट्रपति मैक्रों के समक्ष बहुआयामी चुनौतियां हैं। अगर वो जनअसंतोष को ठीक से हैंडल कर पाए तो ठीक है, वरना फ्रांस जैसे विकसित देश में भी सत्ता परिवर्तन के हालात बनेंगे, जैसा कि नेपाल में हुआ है।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पड़ोसी देशों में अराजकता और भारतीय संविधान की ताकत

नेपाल का उदाहरण सबके सामने है। बीते दिनों वहां की सड़कों पर जिस तरह का आक्रोश देखने को मिला, उसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के सरकार के फैसले ने आग में घी का काम किया। युवा वर्ग, जिसे 'जेन-जेड' कहा जा रहा है, अब केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। संसद भवन तक भीड़ का पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ और नेताओं के घरों पर हमले यह साबित करते हैं कि जनता का धैर्य टूट चुका है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हिंसा थमी नहीं। सेना को कर्फ्यू लगाना पड़ा, फिर भी आंदोलन जारी है।

हम में अपने संविधान पर गर्व है- पड़ोसी देशों को देखिए, वहां क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की यह टिप्पणी हाल ही में संविधान पीठ की सुनवाई में आई। यह वाक्य केवल एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि दक्षिण एशियाई लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति पर गहन चिंतन और चेतावनी भी था। गवई ने नेपाल और बांग्लादेश का हवाला देकर बताया कि जब संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं, जब जनता का भरोसा व्यवस्था से उठता है, तो लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है। भारत का संविधान आज इस मायने में सबसे बड़ी ढाल है कि उसने बार-बार हमें संकटों से निकालकर लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखा।

नेपाल का उदाहरण सबके सामने है। बीते दिनों वहां की सड़कों पर जिस तरह का आक्रोश देखने को मिला, उसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के सरकार के फैसले ने आग में घी का काम किया। युवा वर्ग, जिसे 'जेन-जेड' कहा जा रहा है, अब केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। संसद भवन तक भीड़ का पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ और नेताओं के घरों पर हमले यह साबित करते हैं कि जनता का धैर्य टूट चुका है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हिंसा थमी नहीं। सेना को कर्फ्यू लगाना पड़ा, फिर भी आंदोलन जारी है।

नेपाल में यह अस्थिरता नई नहीं है। 2008 में जब राजशाही खत्म हुई, तो लगा था कि अब लोकतंत्र स्थिरता और विकास का रास्ता खोलेगा। लेकिन हकीकत उलट निकली। पिछले 17 वर्षों में वहां 14 सरकारें बदल चुकी हैं, कोई भी प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। बार-बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों पर विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारें गिराईं और बहाल कीं। संविधान, जो 2015 में लागू हुआ था, वह भी स्थिरता नहीं ला सका। परिणाम यह है कि जनता अब व्यवस्था से मोहभंग कर चुकी है और राजशाही की वापसी की मांग तक उठने लगी है।

बांग्लादेश का परिदृश्य भी कुछ ऐसा ही है। हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और वे कुछ समय के लिए भारत में शरण लेने आईं। यह उस देश की त्रासदी है जिसने 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्रता पाई थी और लोकतांत्रिक भविष्य की उम्मीद जगाई थी। लेकिन वहां लगातार सत्ता संघर्ष, विपक्षी दलों के बीच अविश्वास और चुनावी प्रक्रिया पर सवालों ने संस्थाओं को खोखला बना दिया। जनता का भरोसा टूटने का नतीजा यही होता है कि लोकतंत्र केवल औपचारिकता रह जाता है और सड़क पर हिंसा ही असली राजनीति बन जाती है।

इन हालातों की तुलना में भारत का लोकतंत्र और संविधान सबसे मजबूत उदाहरण बनकर सामने आता है। भारत ने भी संकटों का सामना किया है। 1975 का आपातकाल हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। उस दौर में मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, मीडिया पर सेंसरशिप लगी और विपक्षी नेता जेल में ठूंस दिए गए। लेकिन वही संविधान, वही लोकतांत्रिक चेतना और वही जनता थी जिसने 1977 में इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। और जब जनता ने देखा कि नई सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही, तो 1980 में उन्होंने इंदिरा को फिर से बहुमत से सत्ता में वापस ला दिया। यही संविधान की खूबसूरती है कि वह न केवल नेताओं को उनकी सीमा दिखाता है, बल्कि जनता को भी सही रास्ता चुनने की ताकत देता है।

भारत की न्यायपालिका इस संविधान की सबसे बड़ी प्रहरी रही है। 1990 में मंडल कमीशन का मामला जब देशभर में हिंसा का कारण बना, तब सुप्रीम कोर्ट ने नौ जजों की पीठ बनाकर यह स्पष्ट किया कि आरक्षण पचास प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा और 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखा जाएगा। इससे सामाजिक न्याय और समान अवसर का संतुलन बना रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद देश दंगों की आग में झुलस रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक आस्था भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। 2019 में आया फैसला संवैधानिक मर्यादा में रहा और देश ने बिना बड़े दंगे के उसे स्वीकार किया। इसी तरह 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले रद्द कर दिए। यह संदेश गया कि राष्ट्रीय संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने वाला कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है। यही वह तंत्र है, जिसकी वजह से भारत में जनता का संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा बना रहा, जबकि पड़ोसी देशों में यह भरोसा टूट गया।

भारत का संघीय ढांचा भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन किसी एक को तानाशाह बनने से रोकता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता ने भी लोकतंत्र को सुरक्षित रखा। यही कारण है कि हर पांच साल में सत्ता बदलने का अधिकार जनता के हाथ में रहता है और कोई भी नेता खुद को अजेय मानने की गलती नहीं कर पाता।चीफ जस्टिस की टिप्पणी दरअसल हमें यही याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि यह जनता की ताकत का प्रतीक है। भारत ने हर संकट से संवैधानिक रास्ते से ही बाहर निकलने का सबक सीखा है। इमरजेंसी हो, मंडल हो, बाबरी मस्जिद का विवाद हो या घोटालों का दौर हर बार संविधान ने रास्ता दिखाया।

नेपाल और बांग्लादेश के हालात भारत के लिए भी चेतावनी हैं। अगर कभी संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर हुई या नेताओं ने जनता का भरोसा तोड़ा, तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन अब तक भारत ने संविधान को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया है। यही वजह है कि जब पड़ोसी देश अराजकता और अस्थिरता में झुलस रहे हैं, भारत का लोकतंत्र और संविधान मजबूती का प्रतीक बनकर सामने आता है।नेपाल का 'जेन-जेड' आंदोलन बता रहा है कि नई पीढ़ी अब पुरानी राजनीति और पुराने तौर-तरीकों को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हिंसा और आगजनी समाधान नहीं है। भारत का अनुभव यह कहता है कि परिवर्तन का रास्ता केवल संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही निकलता है। जनता को अधिकार भी यही देता है और जिम्मेदारी का बोध भी यही कराता है।

मुख्य न्यायाधीश गवई की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ गर्व करने की बात नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए चेतावनी भी है। अगर हमने अपने संविधान और संस्थाओं की रक्षा नहीं की, तो हम भी उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहाँ आज नेपाल और बांग्लादेश खड़े हैं।भारत की उपलब्धि यही है कि संविधान को व्यवहार में उतारा गया है। यह किताब में बंद दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जिसने 75 वर्षों से देश को दिशा दी है। इसी संविधान ने हमें लोकतंत्र के अंधेरों से बार-बार रोशनी की ओर पहुँचाया है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गर्व से खड़ा है, जबकि पड़ोसी देशों की स्थिति हमें यह याद दिलाती है कि अगर संविधान कमजोर हो, तो लोकतंत्र केवल एक छलावा बन जाता है।

सामयिक

संजीव शर्मा

लेखक स्तंभकार हैं।

ये जेन जी, जेन जी क्या है...ये जेन जी?

जब से नेपाल में आंदोलन और सत्ता में बदलाव की खबरें मीडिया में दौड़ रही हैं तब से 'जेन जी' और 'नेपो किड्स' जैसे शब्द घर-घर में सुनाई देने लगे हैं। हालांकि नेपो किड्स हमारे देश में नया शब्द नहीं है क्योंकि मनोरंजन जगत और खासतौर पर बॉलीवुड, खेल, व्यवसाय एवं राजनीति जैसे तमाम क्षेत्रों में इसका भरपूर इस्तेमाल होता आ रहा है।

सामान्य रूप से समझे तो नेपो किड्स शब्द नेपोटिज्म से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ है भाई-भतीजावाद। यह तमगा उन युवाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने परिवार के प्रभाव के कारण राजनीति,मनोरंजन, फिल्म, खेल, व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इन पर यह आरोप लगता है कि वे प्रतिभा या मेहनत के बजाय अपने परिवार के नाम पर सफलता हासिल कर रहे हैं। हालांकि कई मामलों में यह बात सही नहीं है क्योंकि नेपो किड्स में कई युवा वाकई प्रतिभाशाली होते हैं और वे अपनी लगन, मेहनत और कौशल से लंबी रेस का घोड़ा साबित होते हैं।

जहां तक मौजूदा वक्त के सबसे चर्चित शब्द 'जेन झेड' या जेनरेशन झेड की बात है तो यह शब्द आमतौर पर उन युवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। जैसे भारतीय संदर्भ में परदादा, दादा, पिता और बेटे के जरिए पीढ़ियों को समझा जाता है उसी तरह पश्चिमी संदर्भ में पीढ़ियों को अलग अलग नाम से वर्गीकृत किया गया है। फिलहाल जेन जी सबसे युवा पीढ़ी है जो डिजिटल युग में पग कर एवं रच बसकर तैयार हुई है। यह पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है इसलिए कुछ लोग इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं। जेन झेड को तकनीकी दक्षता, सामाजिक जागरूकता और वैश्विक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता के लिए भी जाना जाता है।

ऐसा भी नहीं है कि पीढ़ियों का नामकरण कोई पहली बार हो रहा है। दशकों से पश्चिमी समाज में बदलती पीढ़ियों को उनके दौर और तात्कालिक घटनाओं के मुताबिक अलग अलग दिलचस्प नामों से संबोधित किया जाता रहा है। मसलन नामकरण की इस श्रृंखला की सबसे पहली एवं 1883-1900 के बीच जन्मी पीढ़ी को 'लॉस्ट जेनरेशन' कहा जाता है । यह पीढ़ी प्रथम विश्व युद्ध के समय की थी। इस समूह ने युद्ध और सामाजिक उथल-पुथल का सामना किया। इसके बाद की पीढ़ी को नाम मिला 'ग्रेटेस्ट जेनरेशन' । इसमें 1901-1927 के बीच जन्में लोगों को शामिल किया गया। देशभक्ति, कठिन परिश्रम और सामूहिक बलिदान से अपनी पहचान बनाने वाली इस पीढ़ी ने प्रथम विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव किया था।

इसके बाद नंबर आता है 'साइलेंट जेनरेशन' का। हालांकि इस नाम का इनके चुप/मौन रहने से कोई मतलब नहीं है बल्कि मौन रहकर परिश्रम करने से है। इस पीढ़ी में 1928-1945 के बीच जन्में लोग शामिल किए गए । इस पीढ़ी ने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण का दौर देखा है और अपनी मेहनत से अपना संसार रचा था। साइलेंट जनरेशन के बाद आई पीढ़ी के नामकरण की वजह भी बहुत ही दिलचस्प है। इन्हे 'बेबी बूमर्स' कहा जाता है और इसमें 1946-1964 के बीच जन्में लोग शामिल हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में एकाएक हुई वृद्धि के कारण इस पीढ़ी को यह नाम मिला। यह पीढ़ी आर्थिक समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन और उपभोक्तावाद के लिए भी जानी जाती है।

मौजूदा वक्त में अपनी कलम, लेखन, परिश्रम, विचारों और आविष्कारों से दुनिया को समृद्ध करने वाली और अब अधेड़ हो चली पीढ़ी को 'जेनरेशन एक्स' कहा जाता है। इसमें 1965-1980 के बीच जन्में हम जैसे तमाम लोग शामिल हैं। हमारी यह पीढ़ी इस मामले में सबसे खास है कि इसने परंपराओं और तकनीकी बदलावों को साथ-साथ जिया है। जेन एक्स ने लैंडलाइन फोन से लेकर पेजर एवं मोबाइल फोन के विकास तक और कैसेट से फ्लॉपी,सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और अब क्लाउड स्टोरेज तक का लंबा परन्तु तेजी से बदलता सफर तय किया है।

इसके बाद आती है 'जेनरेशन वाय' अर्थात् वो लोग जिन्होंने 1981-1996 के बीच जन्म लिया है। हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे परिवार के बड़े बच्चे शामिल हैं। यह पीढ़ी डिजिटल क्रांति के शुरुआती दौर में जवान हुई है और तकनीक समझ के साथ इसके अनुभवों से भी सराबोर है।

अब आती है बारी बहुचर्चित 'जेनरेशन झेड' या जेन जी की। यह हमारी युवा पीढ़ी है क्योंकि इन्होंने 1997-2012 के बीच जन्म लिया है। मोबाइल, गेमिंग, सोशल मीडिया में डूबती उतराती इस पीढ़ी के सदस्य अधिकतम 25 से 28 साल के युवा हैं और इन्हें पढ़ाई, नौकरी, बढ़िया लाइफ और व्यक्तिगत हितों की सबसे ज्यादा फिक्र है। इसलिए यह पीढ़ी दुनिया भर में धमा चौकड़ी मचाए हुए है।

ऐसा नहीं है कि पीढ़ियों का यह वर्गीकरण जेन जी पर आकर रुक गया है बल्कि इनके पीछे पीछे एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है जिसे 'जेनरेशन अल्फा' नाम मिला है। इसमें 2013 से लेकर मौजूदा साल यानि 2025 तक पैदा हुए बच्चे शामिल हैं। यह मानव सभ्यता की सबसे नवीनतम पीढ़ी है, जो पूरी तरह से 21वीं सदी में जन्मी है।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पीढ़ियों का यह वर्गीकरण मोटे तौर पर जन्म वर्ष, सामाजिक-आर्थिक घटनाओं, और सांस्कृतिक बदलावों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक पीढ़ी को उस समय की प्रमुख घटनाओं और मूल्यों के आधार पर परिभाषित किया जाता है और उसी के मुताबिक उनका नामकरण किया जाता है। बस, सोचने वाली बात यह है कि जब जेन जी दुनिया भर में ऐसा जबरदस्त हड़कंप मचाए हुए है तो जनरेशन अल्फा क्या और कितना कमाल नहीं करेगी।

हमारा लोकतंत्र परिपक्व है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

सीमावर्ती देश में व्याप्त हिंसक गतिविधियों के बीच हम यूं राहत की सांस ले सकते हैं कि राजनीतिक स्तर पर चाहे किसी से भी कितने भी मतभेद क्यों न हो, हमारे यहां नागरिकों का मताधिकार ही सत्ता परिवर्तन हेतु निर्णायक भूमिका का निर्वहन करता है। हालांकि मानवीयता के नाते हम पड़ोसी देश में सुख शांति तथा कानून और व्यवस्था स्थापित होने की कामना करते है। खैर, दरअसल यह एक मानवीय स्वभाव होता है कि किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के प्रति जो भी उचित या अनुचित कदम उठाया गया हो, उसकी सफलता के चलते उसके अनुकरण का विचार आने लगता है। ऐसा होने पर कभी-कभी सही काम को करने के लिए गलत तरीके भी अपना लिए जाते हैं।

इसलिए कहीं ऐसा न हो कि व्यवस्था से नाराज तबका हमारे यहां कहीं आपा खो बैठे। हालांकि यह नामुमकिन है, लेकिन क्या पता कल को क्या हो बैठे, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल तथा उसके नेताओं को अपने द्वारा प्रयुक्त शब्दावली में अत्यधिक शालीनता बरतने की जरूरत है। दरअसल राजनीति में परस्पर विरोधी तबका एक दूसरे पर दिल और दिमाग से अनियंत्रित होकर तमाम तरह की घेराबंदी करने लगा हैं। इसके लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो सहारा लिया ही जाता रहा है, लेकिन नई पीढ़ी काफी हद तक अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए सोशल मीडिया पर आश्रित होती जा रही है।

इसके चलते सोशल मीडिया भी अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम बन गया है। जिस पर बिना किसी विशेष रोक-टोक के कोई भी किसी पर भी किसी भी मामले में पत्थर उछाल सकता है। हालांकि गलती मानना या मनवाने का प्रावधान भी होता है। लेकिन काफी हद तक कमान से निकला तीर अपना काम कर चुका होता है। इस स्थिति के चलते बदलते दौर के सार्वजनिक जीवन में नैतिकता एवं व्यवहारिकता के उच्च स्तरीय मापदंड का अनुपालन आज के दौर की पहली जरूरत है। दरअसल किसी भी दल या व्यक्ति विशेष का समर्थन या विरोध हो, तो उसका भी एक शालीन तरीका होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय देश में ऐसा नहीं हो रहा। यह चिंता का विषय है।

लोकतंत्र की राजनीति में राजनीतिक दल एवं उसके नेताओं के अंतर्मन में सत्ता प्राप्ति या सत्ता के लिए निर्णायक भूमिका में आने की भावना होती है। और यह बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन विगत 10 वर्षों से राजनीति में इतनी कलुषता और वैमनस्यता व्याप्त होने लगी है, जो राजनीति में परस्पर एक दूसरे पर गंभीर लांछन लगाने की हद तक बढ़ चुकी है। राजनीति में नीति और सिद्धांतों का मतभेद व्यक्तिगत शत्रुता की भांति दिखाई देने लगा है। हालांकि इस स्थिति के लिए किसी एक दल या उसके नेता को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कमोबेश हर एक राजनीतिक दल तथा उसके नेता परस्पर अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखे हुए है।

राजनीतिक शुचिता एवं पवित्रता का अब वह दौर दिखाई नहीं देता, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक दो-तीन दशकों तक दिखाई देता था। परतंत्र भारत में विदेशी हुकूमत की रीति-नीति पर चलने की एक होड़ सी दिखाई देती है। विभिन्न धर्म वर्ग व जाति में अनावश्यक टकराव की स्थिति उत्पन्न होने देना, हर एक घटना या दुर्घटना का राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा करना और वह सब हर संभव प्रयत्न करना जिसके चलते विरोधी की छवि को कलंकित किया जा सके, दरअसल इन दिनों यही राजनीति का चरित्र बनकर रह गया है। और तो और परदेस में जाकर देश की दशा और दिशा को लेकर अनावश्यक बयानबाजी करना आखिर क्या दर्शाता है ? मुद्दे की बात यह कि आम नागरिकों के मन मे यदि सत्ता एवं व्यवस्था के प्रति गहन नाराजगी के भाव हो या कि सत्ता तंत्र के क्रियाकलापों अथवा काम करने या न करने के तौर तरीकों को लेकर मन ही मन गहरा उबाल हो, तो भी उसे और अधिक बढ़ावा न दिया जाए। इसके स्थान पर नागरिकों को हर एक दृष्टि से जागरूक करने की दिशा में ही विशेष प्रयत्न किए जाएं, तो यह लोकतंत्र में लोकतंत्र के सुरक्षित रहने के प्रति जन जन को निश्चिंत कर सकेगा। इसके लिए तमाम विरोधी दल एवं उसके नेताओं के लिए वाणी एवं व्यवहार का संयम रखना बहुत जरूरी है। साथ ही सत्तापक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी हर एक आलोचना को लेकर निष्पक्ष एवं तटस्थ भाव से आत्म चिंतन करें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

अरुण अर्णव खरे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

चैट जीपीटी और प्रेम-पत्र

नौरंगीलाल की ज़िंदगी में हाल ही में प्रेम का रंग घुला था। वह सोशल मीडिया पर बनी महिला-मित्र को प्रेम-पत्र लिखकर चौंकाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि प्रेम-पत्र में प्रेमिका को किस उपमा से संबोधित करें। काफी माथापच्ची के बाद उनके मन में ख्याल आया -'चैट जीपीटी का बड़ा नाम सुना है, क्यों न उससे ही मदद ली जाए?'

नौरंगीलाल ने 'आस्क एनीथिंग' बॉक्स में टाइप किया -'मैं परेशान हूँ, प्रेयसी को किस उपमा से संबोधित करूँ? क्या आप मदद कर सकते हैं?'

पल भर में ही उत्तर आ गया - 'बिल्कुल! प्रेयसी को संबोधित करने के कई प्यारे, रोमांटिक और आत्मीय तरीके हैं। आप प्रेयसी के स्वभाव और रिश्ते की घनिष्ठता के अनुसार चुन सकते हैं। जैसे प्यार भरे संबोधनः जान, रानी, प्राणप्रिय, मेरी धड़कन। कवितामय संबोधनः चाँदनी, गुलाबो, नूर-ए-नजर, रूह की रोशनी। चुलबुले संबोधनः पगली, मिस स्माइल, गुड़िया। फिल्मी संबोधनः दिलरुबा, जानम, मेरी जां, जानेमन। क्या आप चाहेंगे कि मैं उपरोक्त किसी एक संबोधन के अनुरूप आपके लिए लव लेटर का ड्राफ्ट तैयार कर दूँ।'

नौरंगीलाल गदगद हो गए - 'वाह! चैट जीपीटी तो उम्मीद से ज्यादा तेज और मददगार निकला। उन्होंने तुरंत अपने मन की बात कह दी - 'नूर-ए-नजर, संबोधन के साथ प्रेम-पत्र लिख दीजिए'।

कुछ क्षणों में स्क्रीन पर प्रेम-पत्र उभर आया - 'नूर-ए-नजर [नाम], तुम्हें पत्र लिखते हुए शब्द भी तुम्हारे नाम की तरह मीठे लगने लगे हैं। तुम्हारी मुस्कान याद आते ही सारी थकान गायब हो गई है। तुमसे चैट करना, मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। तुम्हारे पास होने की कल्पना से ही लगता है जैसे दुनिया की सारी अधूरी चीजें पूरी हो गई हों। तुम्हारी दोस्ती मेरा सबसे बड़ा संबल है। जल्दी ही तुमसे मिलने की उम्मीद में, तुम्हारा अपना ही'।

पत्र पढ़कर नौरंगीलाल आश्चर्य से वाह-वाह कर उठे। पत्र के नीचे फिर एक नोट था - 'क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी कवितामय बना दूँ, या हल्का-फुल्का शरारती अंदाज भी जोड़ दूँ?'

नौरंगीलाल सोच में पड़ गए, उन्हें लगा - 'पत्र कुछ ज्यादा ही साहित्यिक हो गया है, क्यों न हल्के-फुल्के पत्र के लिए अनुरोध किया जाए।'

अनुरोध का तुरंत पालन हुआ - 'ठीक है। अब मैं वही पत्र थोड़ा शरारती और हल्के-फुल्के अंदाज़ में लिख देता हूँ।'

'तुम्हारी हँसी सुनने को दिल ऐसा बेचैन हो जाता है, जैसे बिना शक्कर की चाय पीने के उपरांत हो जाता है। जब तुम ऑनलाइन आने में देर कर देती हो तो हालत उतनी ही खराब हो जाती है, जितनी नेट स्लो होने पर वीडियो की। कभी-कभी सोचता हूँ कि तुम्हें मैं अपना पासवर्ड बना लूँ, ताकि तुम्हें याद करते ही ज़िंदगी अनलॉक हो जाए। तुम्हारे बिना हर पल साल सरीखा लगता है और तुम्हारे साथ हर पल फाइव जी वाईफाई जैसा तेज दौड़ने लगता है।÷ इसके बाद फिर एक नोट था - 'क्या चाहेंगे कि मैं इसमें थोड़े इमोशंस भी मिला दूँ?'

'जी, मिला दीजिए'

तुरंत एक और ड्राफ्ट सामने आ गया - 'कभी-कभी लगता है कि हमारी कहानी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। फर्क बस इतना है कि यहाँ कैमरा नहीं, सब दिल में रिकॉर्ड हो रहा है। जब तुम दूर होती हो, तो दुनिया स्लो मोशन में चलती है, और पास आते ही फिल्म का क्लाइमैक्स इतनी जल्दी आ जाता है जैसे ढाई घंटे की फिल्म ढाई मिनट में खतम हो गई हो। तुम्हारी याद दिल में फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह बजती रहती है।'

अंत में फिर वही नोट - 'क्या चाहेंगे कि इसे व्हाट्सएप पर भेजने लायक संक्षिप्त बना दूँ?'

'ठीक है, यह भी कर दीजिए'

अगले ही पल स्क्रीन पर छोटा-सा ड्राफ्ट जगमगाने लगा - 'तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लाइन हो - कभी कविता, कभी शरारत, कभी फिल्म का सबसे प्यारा सीन। तुम्हारी मुस्कान मेरी रोशनी है, तुम्हारी यादें मेरी आदत। तुम्हारे बिना दिल सूना-सूना रहता है और तुम्हें देखते ही आनंद से भर जाता है।' इसके नीचे था एक और नोट - 'क्या चाहेंगे कि इसका और भी छोटा 'लव नोट' बना दूँ, जो स्टेटस में डाल सकें?'

'ठीक है'

और ये रहा आपका चाहा 'लव नोट' - 'तुम मेरी मुस्कान की वजह हो, मेरे सपनों की धड़कन हो, और मेरी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो।' अंत में फिर वही चिर-परिचित नोट - 'क्या चाहेंगे कि ऐसे पाँच और लव नोट्स बना दूँ, जिन्हें अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल कर सकें?'

अब नौरंगीलाल का सब्र टूट गया। झल्लाहट में लिखा और सिर पकड कर बैठ गए - 'अब बस करो महाराज! गलती हो गई तुमसे पूछकर। तुम तो प्रेमपत्र के साथ जनाज़ा निकालने पर अमादा हो।'

नौरंगीलाल कुर्सी से उठने ही वाले थे कि स्क्रीन फिर से चमक उठी - 'क्या आप चाहेंगे कि जनाज़ा निकलने पर उसके साथ रखने लायक एक छोटा-सा नोट भी बना दूँ?'

नेपाल

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक शोधार्थी हैं।

क्या नई पीढ़ी बालेन शाह जैसे चेहरों के साथ जातीय ढांचे को बदल पाएगी?

1990 में नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी हुई थी। जनता को उम्मीद थी कि अब सत्ता में विविधता आएगी और हर समुदाय को बराबरी का अवसर मिलेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 1990 से अब तक नेपाल ने 13 प्रधानमंत्री देखे। इनमें से 10 पहाड़ी ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय रहे। यानी 35 प्रतिशत मधेशियों की आबादी होने के बावजूद एक भी मधेशी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जनजातीय और आदिवासी समूह संसद में मौजूद हैं, लेकिन उनके नेता केवल प्रतीकात्मक पदों तक सीमित रहे। दलित और महिलाएँ तो आज भी सत्ता के सबसे हाशिये पर खड़ी हैं। यह तस्वीर बताती है कि नेपाल का लोकतंत्र कितनी गहरी जातीय असमानता से ग्रस्त है। लोकतंत्र के नाम पर चेहरे तो बदले, लेकिन सत्ता का चरित्र वही रहा- ब्राह्मण और क्षत्रिय केंद्रित।

नेपाल हिमालय की गोद में बसा छोटा-सा देश है। आकार में भले छोटा हो, लेकिन राजनीति और जातीय समीकरण के लिहाज से इसकी जटिलता किसी बड़े देश से कम नहीं। नेपाल पिछले तीन दशकों से लोकतंत्र का प्रयोग कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह लोकतंत्र अब भी अधूरा है। सत्ता और संसाधनों पर एक ही वर्ग का कब्ज़ा है- पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियाँ। संसद से लेकर प्रशासन और सेना तक, हर जगह यही जातियाँ हावी हैं। मधेशी, जनजातीय, दलित और महिलाएँ अब भी सत्ता की सीढ़ियों के निचले पायदान पर खड़ी हैं।

1990 में नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी हुई थी। जनता को उम्मीद थी कि अब सत्ता में विविधता आएगी और हर समुदाय को बराबरी का अवसर मिलेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 1990 से अब तक नेपाल ने 13 प्रधानमंत्री देखे। इनमें से 10 पहाड़ी ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय रहे। यानी 35 प्रतिशत मधेशियों की आबादी होने के बावजूद एक भी मधेशी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जनजातीय और आदिवासी समूह संसद में मौजूद हैं, लेकिन उनके नेता केवल प्रतीकात्मक पदों तक सीमित रहे। दलित और महिलाएँ तो आज भी सत्ता के सबसे हाशिये पर खड़ी हैं। यह तस्वीर बताती है कि नेपाल का लोकतंत्र कितनी गहरी जातीय असमानता से ग्रस्त है। लोकतंत्र के नाम पर चेहरे तो बदले, लेकिन सत्ता का चरित्र वही रहा-ब्राह्मण और क्षत्रिय केंद्रित।

नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही वह नई पीढ़ी है जिसे जनरेशन- कहा जाता है। यह सोशल मीडिया, पॉप कल्चर और वैश्विक राजनीति से जुड़ी हुई है। इनके लिए जाति और वंश की राजनीति पुरानी और अप्रासंगिक है। यह पीढ़ी पारदर्शिता चाहती है, समान अवसर चाहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव को केवल सोचती नहीं बल्कि मांग भी करती है। यही कारण है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह आज नेपाल के युवाओं के बीच परिवर्तन का प्रतीक बन चुके हैं।

2022 में जब बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता तो यह केवल एक चुनाव नहीं था, बल्कि

सत्ता की पुरानी धारणाओं पर सीधी चोट थी। काठमांडू दशकों से मुख्यधारा की पार्टियों-नेपाली कांग्रेस, ML और माओवादी केंद्र–का गढ़ माना जाता था। लेकिन शाह ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सबको चौंका दिया। वे न तो परंपरागत राजनीति से आए थे और न ही किसी जातीय वंश से जुड़े थे। उनकी पृष्ठभूमि हिप-हॉप कलाकार और इंजीनियर की थी। वे मधेशी भी हैं और बौद्ध भी। यानी हर लिहाज से नेपाल की मुख्यधारा की राजनीति से बिल्कुल अलग। उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि जनता अब विकल्प चाहती है। खासकर युवा पीढ़ी, जो बार-बार जातीय गणित से चलने वाली राजनीति से ऊब चुकी है।

बालेन शाह का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। वे सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं और सीधा संवाद करने का तरीका जानते हैं। नेपाल की मौजूदा राजनीति जहाँ अभी भी भाषण और रैलियों पर निर्भर है, वहीं शाह डिजिटल युग की राजनीति कर रहे हैं। उनका संगीत, उनकी स्पष्ट बातें और उनकी स्वतंत्र छवि युवाओं को तुरंत आकर्षित करती है। यह फर्क बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में पहली बार कोई ऐसा चेहरा सामने आया है जो राजनीति को कूल बना रहा है।

लेकिन सवाल यही है कि क्या नेपाल की पुरानी सत्ता संरचना इतनी आसानी से टूट जाएगी? नेपाली कांग्रेस, रूऔर माओवादी जैसे दल दशकों से सत्ता पर काबिज हैं। इनके नेता ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और इनकी पकड़ प्रशासन, सेना और नौकरशाही तक फैली हुई है। यह पूरा ढांचा बालेन शाह जैसे किसी नेता के लिए दीवार की तरह खड़ा हो सकता है। संभावना है कि शाह को 'अनुभवहीन' या 'पॉपुलिस्ट' कहकर खारिज करने की कोशिश की जाएगी। उनकी स्वतंत्र पहचान पर सवाल उठाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में बैठे लोग कभी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते।

अगर नेपाल बालेन शाह जैसे नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका देता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, बल्कि ऐतिहासिक होगा। नेपाल पहली बार किसी गैर-ब्राह्मण/क्षत्रिय प्रधानमंत्री को देखेगा। यह संदेश जाएगा कि लोकतंत्र केवल नाम का नहीं बल्कि वास्तविक रूप से समावेशी है। मधेशी, जनजातीय और दलित समुदाय को यह विश्वास मिलेगा कि सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी है। युवाओं को लगेगा कि उनकी आवाज़ मायने रखती है।

लेकिन अगर बदलाव की इस मांग को दबाया गया, तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। युवा पीढ़ी पहले ही अधीर है। वे सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी और सपनों को साझा कर रहे हैं। अगर उनकी आवाज़ दबाई गई, तो असंतोष सड़क पर आंदोलन में बदल सकता है। नेपाल ने पहले भी जनआंदोलन देखे हैं और इतिहास गवाह है कि जब जनता चाहती है, तो कोई भी सत्ता ढांचा स्थायी नहीं रह पाता।

नेपाल आज दो राहों पर खड़ा है। एक तरफ पुरानी राजनीति है, जहाँ सत्ता कुछ जातियों के बीच बंटी हुई है। दूसरी तरफ नई राजनीति है, जो समावेशी, पारदर्शी और युवाओं से जुड़ी है। बालेन शाह इस बदलाव का प्रतीक हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या नेपाल जातीय ढांचे वाली राजनीति से आगे बढ़ पाएगा या नहीं।

अगर नेपाल यह कदम उठाता है, तो वह दक्षिण एशिया में एक मिसाल बन सकता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी राजनीति अक्सर वंशवाद और जातीय समीकरण में उलझी रहती है। नेपाल अगर इस ढांचे से बाहर निकलता है, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा होगी। लेकिन अगर पुरानी सत्ता संरचना कायम रहती है, तो लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। युवाओं का भरोसा टूटेगा और यह भरोसा टूटना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है।

नेपाल की राजनीति दशकों से पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के कब्ज़े में रही है। लोकतंत्र आया, चेहरे बदले, लेकिन चरित्र वही रहा। आज की पीढ़ी इसे चुनौती दे रही है। बालेन शाह इसका चेहरा हैं। यह पीढ़ी जाति, वंश और सत्ता के पुराने ढांचे को स्वीकार नहीं करना चाहती। नेपाल का लोकतंत्र अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। या तो यह समावेशी होकर सबको बराबरी देगा, या फिर पुरानी असमानता को जारी रखेगा।

भविष्य का फैसला अब नेपाल की नई पीढ़ी के हाथ में है और उनकी मांग साफ है–अबकी बार राजनीति सबकी, सिर्फ ब्राह्मण-छत्री की नहीं।

मुद्दा

आरबी त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

नेपाल में हिंसक क्रांति के बाद आगे क्या?

संसद भवन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य सरकारी इमारतों, एयरपोर्ट, हिल्टन जैसी बड़ी होटल आदि को तोड़फोड़ आगजनी का निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं शासकों के सरकारी तथा निजी भवनों को इसका शिकार बनाया गया। प्रधानमंत्री ओली को अपना पद छोड़कर हेलीकॉप्टर से किसी सुरक्षित जगह जाना पड़ा। कई मंत्रियों को उनके आवास से हेलीकॉप्टर से निकाला गया। देश के गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों को आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ा। जेलों को तोड़कर सैकड़ों क़ैदियों के भागने, कुछ के बाद में पकड़े जाने की खबरें मीडिया रिपोर्ट में सामने आई। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ खुलेआम मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया।

भारत का पड़ोसी देश नेपाल अपेक्षाकृत शांत (सियासत को छोड़कर) और पर्यटकों का पसंदीदा स्थल। भगवान पशुपतिनाथ वहाँ विराजित हैं जहां साल भर श्रद्धालुओं, सैलानियों का तांता लगा रहता है। आस्था का यह केंद्र फिलहाल बंद है। कहा जाता है 'चल- चल रे काठमांडू मिलेंगे वहाँ शंभू।' कई भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रमुख दृश्यों के फिल्माये जाने का स्थल। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी वहां के कलाकारों ने नाम कमाया।

लेकिन बीते सोमवार से ढाई- तीन दिनों में अचानक ऐसा घटित हुआ जिसकी वहां के शासकों को तनिक भी संभावना नहीं रही होगी। तभी बेफिक्र शासक और व्यवस्था जैसे गहरी नींद से जागे हों और इस अनपेक्षित घटनाक्रम पर हड़बड़ा गये हों। जेन 5 क्रांति के नाम पर युवाओं, विद्यार्थियों का हुजूम आक्रोश में काठमांडू की सड़कों पर उतर आया। फिर घोर अराजकता की पराकाष्ठा न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया तथा अखबारों के जरिये सामने आई वह भयावह थी।

संसद भवन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य सरकारी इमारतों, एयरपोर्ट, हिल्टन जैसी बड़ी होटल आदि को तोड़फोड़ आगजनी का निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं शासकों के सरकारी तथा निजी भवनों को इसका शिकार बनाया गया। प्रधानमंत्री ओली को अपना पद छोड़कर हेलीकॉप्टर से किसी सुरक्षित जगह जाना पड़ा। कई मंत्रियों को उनके आवास से हेलीकॉप्टर से निकाला गया। देश के गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों को आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ा। जेलों को तोड़कर सैकड़ों क़ैदियों के भागने, कुछ के बाद में पकड़े जाने की खबरें मीडिया रिपोर्ट में सामने आई। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ खुलेआम मारपीट कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया।

ठीक ऐसा लगने लगा जैसे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश में कुछ समय पूर्व के घटनाक्रम को दोहराया जा रहा हो। लेकिन क्या महज मीडिया प्लेटफार्म पर बेन लगाने से ही युवाओं, विद्यार्थियों का गुस्सा ऐसे हिंसक उपद्रव के रूप में सामने आ सकता है? ऐसा नहीं बल्कि इसकी वजह वहाँ व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, भाई भतीजावाद और शासकों की संतानों के भारी खर्चों पर विदेशों में पढ़ाई तथा उनकी लक्जीरियस लाइफ स्टाइल को भी इस दबे गुस्से और आक्रोश के पीछे की वजह बताया जा रहा है। सोचें हाल ही में फ्रांस जैसा देश बड़े आंदोलन का शिकार बन सकता है तो नेपाल तो सिर्फ तीन करोड़ की आबादी का

छोटा देश है।

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक नेपाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों की संख्या 34 तथा घायलों की संख्या 1338 तक पहुंचने की खबरें हैं। वहां अंतरिम सरकार के गठन के लिये गहमागहमी और चर्चा जारी है। सेना ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल शांति की अपील कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर उन्हें भी पद से त्यागपत्र देने की आवाजें उठ रही हैं। अंतरिम सरकार पर जेन 5 गुटों में बंटती नजर आ रही है तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजशाही समर्थक भी अपना दबाव बनाने में लगे हैं। वहां फंसे भारतीयों, पर्यटकों को भारत लाया जा रहा है।

अफवाहों और आशंकाओं के बीच वहां की पल प्रतिपल बदलती स्थिति पर अभी निश्चित तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। घटनाक्रम का प्रभाव पड़ोसी देशों खासकर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। नेपाल से हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। बिहार में निकट भविष्य में विधान सभा के चुनाव हैं। सो, वहां के हालात पर भारत को सतर्कता बरतकर नजर रखना लाजमी है। आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा कि नेपाल की शासन व्यवस्था कैसी और किसके हवाले रहेगी। जो भी हो वहां लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आंच ना आये यही उम्मीद की जा सकती है।

पितृ पक्ष

गरिमा विजयवर्गीय

लेखक पत्रकार हैं।

अमरकंटक -देश का एकमात्र स्थान, जहां 96 प्रकार के पिंडदान की व्यवस्था

अमरकंटक में पितरों के पिंडदान का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् वायु पुराण में मिलता है, इसके अनुसार कुछ विशिष्ट स्थान पितरों के पिंडदान के लिए अतिश्रेष्ठ माने गए हैं। ये स्थान सरोवर, नदियां कुछ भी हो सकते हैं। इनमें प्रथम स्थान के तौर पर अमरकंटक की गणना की जा सकती है। वायु पुराण के अनुसार श्री बृहस्पति कहते हैं कि अमरकंटक पर कुशाओं पर जो एक बार पिंडदान कर देता है, वो पितरों को संतुष्ट करने वाला अक्षय श्राद्ध होता है। अमरकंटक में एक बार भी पितरों की अर्चना करने पर स्वर्ग सुलभ है।

पितरों के पिंडदान और तर्पण की जब बात आती है, तब सदा बिहार के गया जी का ही उल्लेख आता है, लेकिन कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मध्यप्रदेश स्थित मां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पितरों के पिंडदान के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में अग्रणी है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी का जल तीन दिन में पवित्र बनाता है, यमुना जल सात दिन में पावन बनाता है, गंगा जल में स्नान तत्काल पवित्र बनाता है, किंतु नर्मदा नदी एकमात्र वह नदी है, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों को पवित्र बनाती है।

अमरकंटक में पितरों के पिंडदान का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् वायु पुराण में मिलता है, इसके अनुसार कुछ विशिष्ट स्थान पितरों के पिंडदान के लिए अतिश्रेष्ठ माने गए हैं। ये स्थान सरोवर, नदियां कुछ भी हो सकते हैं। इनमें प्रथम स्थान के तौर पर अमरकंटक की गणना की जा सकती है। वायु पुराण के अनुसार श्री बृहस्पति कहते हैं कि अमरकंटक पर कुशाओं पर जो एक बार पिंडदान कर देता है, वो पितरों को संतुष्ट करने वाला अक्षय श्राद्ध होता है। अमरकंटक में एक बार भी पितरों की अर्चना करने पर स्वर्ग सुलभ है।

देश भर में कुल 48 स्थान पिंडतीर्थ के तौर पर निर्धारित हैं, लेकिन अमरकंटक देश का एकमात्र वो स्थान है, जहां 96 प्रकार के पिंडदान की व्यवस्था है। शास्त्रों के अनुसार पिंडदान के लिए नदियों का संगम होना आवश्यक है, इस दृष्टि से देखें तो अमरकंटक पंचप्रयाग की संज्ञा पाए हुए हैं। यहां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पहले दो नदियों गायत्री-सावित्री का संगम होता है। इसके बाद ये दोनों नदियां नर्मदा, कपिला, वैतरणी और अंत में ऐरंड नदी में जाकर मिलती हैं। इस प्रकार अमरकंटक पंचप्रयाग है। ऐरंड नदी का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। अमरकंटक में सभी पूर्ववर्ती नदियां जिस स्थान पर आकर ऐरंड में मिलती हैं, उस स्थान की महिमा सर्वाधिक मानी गई है। ऐरंड का माया से निवृत्ति दिलाने वाली नदियों के रूप में वर्णन उल्लेखित है। ऐसे में इस संगम पर एक बार पिंडदान का वही फल प्राप्त होता है, जो 16 बार गया जी में पिंडदान के बाद प्राप्त होता है।

यहां आकर ये भ्रांति भी टूट जाती है कि केवल मृत व्यक्तियों के नाम पर ही पिंडदान किया जा सकता है। अमरकंटक के मुख्य मंदिर नर्मदा कुंड के पारंपरिक प्रधान पुजारी वंदे महाराज बताते हैं कि अमरकंटक में मनोकामना प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति समेत अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए पिंडदान की व्यवस्था है। अधिकतर पिंडदान पितृ पक्ष के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। यहां पहले पिंडदान की व्यवस्था सिर्फ मंदिर में ही थी, लेकिन अब संपूर्ण अमरकंटक में पांच ऐसे स्थान हैं, जहां विभिन्न प्रकार के पिंडदान से मोक्ष प्राप्ति होती है। हालांकि नर्मदा कुंड के गर्भगृह स्थान में पिंड दान अब भी सीधे बैकुंठ प्राप्ति का जरिया माना गया है।

स्कंद पुराण के रेवा खंड में मां नर्मदा के धरती पर अवतरित होने की कथा है। इसके अनुसार चंद्रवंश के चक्रवर्ती राजा पुरुरवा ने महादेव से विशेष आराधना कर मां नर्मदा को धरतीलोक पर उतारने का आग्रह किया। महादेव ने आठ पर्वतों को बुला कर पूछा कि कौन नर्मदा के वेग को वहन करने में सक्षम है, जिसके बाद मां नर्मदा विंध्यपर्वत पर उतरीं। मां नर्मदा ने विंध्यपर्वत के रास्ते धरती पर उतर कर राजा पुरुरवा से अपने जल को स्पर्श करने को कहा, उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने मां नर्मदा के पवित्र जल से अपने पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। रेवा खंड के अनुसार मां नर्मदा के जल से पितरों का तर्पण करने पर पुरुरवा के पूर्वज उस परम पद को प्राप्त हुए, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रेवा खंड में ऐसे और भी कई प्रसंग हैं, जो बता रहे हैं कि मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में पितरों के तर्पण की महिमा अन्यत्र कहीं तर्पण से कहीं अधिक फलदायी है। एक प्रसंग चंद्रवंश के राजर्षि हिरण्यतेजा का भी है, जिन्होंने पितरों के कष्ट देखकर मां नर्मदा के जल से उनका तर्पण कर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। कहा गया है कि संसार में जब कोई नदी नहीं थीं, तब पूर्वजों का तर्पण पोखरों में होता था। उसी समय हिरण्यतेजा ने घोर तप कर नर्मदा को वरदान रूप में मांगा और नर्मदा जल से पितरों का तर्पण किया।

अमरकंटक, मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा ये कस्बा नर्मदा के साथ ही सोन नदी का भी उद्गम है। ये क्षेत्र मैकल पर्वत श्रृंखला से भी आच्छादित है, इसी कारण ही नर्मदा का एक नाम मैकल सुता भी है। लगभग 12 फुट की गहराई के एक कुंड से निकलती हैं यहां नर्मदा, जिसे अब पूरी तरह कवर कर दिया गया है। कोटितीर्थ मंदिर समूह नाम के इस स्थान पर स्थित इस नर्मदा कुंड के चारों ओर असंख्य शिवलिंग हैं। समूचा मंदिर परिसर अनेक सफेद मंदिरों से बना है। इसी मंदिर परिसर के पास ऐतिहासिक महत्व के कलचुरी वंश के 16वीं शताब्दी के पुरातत्व संरक्षित मंदिर समूह भी हैं। उद्गम के कुछ आगे चलकर नर्मदा नदी की धारा कपिलधारा के नाम से पहचानी जाती है, जो नर्मदा का पहाड़ों से मैदान तक के सफर का पहला जलप्रपात है। इसी क्रम में आगे दुग्ध धारा और इसी प्रकार के और कई जलप्रपात हैं, जिनके रास्ते नर्मदा डिंडोरी और फिर आगे के मैदानी इलाकों का सफर तय करती हैं।

किवदंतियां किस प्रकार दैवीय अस्तित्वों को जन-जन में स्वीकार्य बनाने में अहमियत रखती हैं, ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देता है 'नर्मदा माई की बगिया' में जाकर। किवदंती है कि इस स्थान पर नर्मदा अपने बचपन में खेला करतीं थीं। गगनचुंबी पेड़ों से घिरे इस स्थान पर उनकी सखी गुल बकावली औषधि की झाड़ियां थीं। यहां ये औषधि अब भी बड़ी मात्रा में है, इसके फूल का अर्क नेत्ररोग के लिए उपयोगी बताया जाता है। अमरकंटक का सोनमुड़ा वो स्थान है, जहां के एक कुंड से सोन नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा से अलग ये नदी दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में हुई 400 बच्चों की स्क्रीनिंग

सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

बैतूल। पीएम श्री केंदीय विद्यालय बैतूल में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में सिकल सेल एनीमिया की प्रारंभिक पहचान और इसके प्रति बच्चों में जागरूकता फैलाना था। इस शिविर में विद्यालय के 400 से अधिक छात्र-छात्राओं की स्क्रीनिंग की गई। बच्चों ने भाग लेते हुए अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। सिकल सेल से जुड़ी महत्वपूर्ण

जानकारियां भी प्राप्त की। स्क्रीनिंग में एक बच्चा सिकल सेल वाहक निकला। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम 2047 के तहत कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी डॉ अंकिता सीते और उनकी टीम ने इस शिविर में सिकल सेल और एनीमिया से संबंधित जानकारी बच्चों को दी। बच्चों में सिकल सेल एनीमिया की समय पर पहचान करना करने को लेकर उसके लक्षण बताए। डॉ अंकिता सीते ने बताया कि शिविर में आनुवांशिक बीमारियों की जानकारी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जांच ही बचाव है, इसका का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। समय पर जांच होने से बीमारी को नियंत्रित करने में आसानी होती है। इस शिविर में बैतूल सीएमएचओ डॉ मनोज हुरमाडे,बीएमओ सेहरा डॉ केदार का मार्गदर्शन रहा । जिले में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए विभिन्न तरीके से कार्य किया जा रहे हैं ।खास तौर पर स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग के साथ ही उन्हें इस बीमारी के लक्षण बताए जा रहे हैं। प्रिंसिपल श्री पांडेय ने स्वास्थ्य विभाग की सराहना करते हुए कहा कि इस शिविर से बच्चों और उनके विभागों में जागरूकता आएगी।

ओम आयुर्वेदिक कॉलेज में पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए विद्यार्थियों ने बताया आहार का महत्व

आयुर्वेद उत्सव के अंतर्गत रंग-बिरंगे पोस्टर से दिया सेहत का संदेश

बैतूल। ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सारनी में 10वां आयुर्वेद दिवस सप्ताह आयुर्वेद जन-जन के लिये, पृथ्वी के कल्याण के लिये विषय पर उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस श्रृंखला में 12 सितंबर को महाविद्यालय परिसर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर आहार एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

लाना और आयुर्वेद की जीवनशैली को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना रहा। इस आयोजन में महाविद्यालय के नोडल अधिकारी डॉ. शशिभूषण साहू ने प्रतियोगिता को संयोजित कर छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया और आहार एवं स्वास्थ्य विषय पर अपने-अपने पोस्टर के माध्यम से विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति की। इस अवसर पर महाविद्यालय के कोषाध्यक्ष सोनू पाल, अध्यक्ष गणेश मालवी, उपप्राचार्य प्रोफेसर डॉ. राजकुमार मिश्रा, रीडर डॉ. संदीप पाल, डॉ.कमलेश सोनारे, व्याख्याता डॉ. नरेन्द्र नरवरे, डॉ. स्नेहल इंगले, डॉ. डाली झाड़े और डॉ. प्रियंका पांडे भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों के कार्यों की सराहना की और आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार हेतु इस प्रकार की रचनात्मक प्रतियोगिताओं को समय की आवश्यकता बताया। प्रतियोगिता में प्रस्तुत किए गए पोस्टरों में पौष्टिक आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सात्विक भोजन और आयुर्वेदिक आहार शैली जैसे विषयों को सुंदर चित्रण के साथ दर्शाया गया, जिससे यह आयोजन जन-जागरूकता की दृष्टि से भी बेहद प्रभावी सिद्ध हुआ। आयुर्वेद सप्ताह के तहत महाविद्यालय द्वारा विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला आगामी दिनों तक जारी रहेगी, जिनका उद्देश्य आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को आधुनिक युग के साथ जोड़ते हुए जन-जन तक पहुंचाना है।

चिचोली में आयोजित रोजगार मेले में 147 युवाओं का हुआ चयन

बैतूल। मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में युवा संगम के तहत जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला 12 सितम्बर को नगरपालिका ऑडिटोरियम, चिचोली में आयोजित किया गया। जिला रोजगार कार्यालय बैतूल, आईटीआई बैतूल एवं जिला व्यापार एवं उद्योग

केन्द्र बैतूल द्वारा आयोजित इस मेले में कुल 218 आवेदकों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 14 कंपनियों द्वारा 147 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन कर उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा बाई सज्जन सिंह उइके, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती वर्षा रितेश मालवीय, उपाध्यक्ष श्रीमती वर्षा संजय आवलेकर सहित प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। इसके साथ ही मेले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 218 आवेदकों को कैरियर काउंसलिंग दी गई, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा 2 हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदाय किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 18 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें से 3 सिकलसेल तथा 15 अन्य बीमारियों की जांच की गई।

राजस्व वसूली में गिरावट पर सीएमओ सख्त निरीक्षकों को वसूली का दिया लक्ष्य

लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा नहीं तो रोका जायेगा वेतन

संजय द्विवेदी, बैतूल। नगरपालिका के राजस्व वसूली में लगातार गिरावट आ रही है,और इसे लेकर सीएमओ सख्त हो गये है। यहां तक कि सीएमओ ने पिछली बैठक में चेतावनी दी कि यदि राजस्व निरीक्षकों द्वारा निर्धारित समयसीमा में वसूली नहीं बढ़ई, तो शोकाज नोटिस और वेतन काटने जैसी कार्रवाही तक की जायेगी। दरअसल नगरपालिका के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व मांग 11 करोड़ 63 लाख रुपए की है, जबकि अप्रैल से अभी तक महज 1 करोड़ 62 लाख रुपए ही वसूले जा सके हैं। यही कारण है कि नगरपालिका की वित्तीय स्थिति दिनोंदिन खराब होते जा रही है। नपा सीएमओ सतीश मटसेनिया ने साफ कहा कि राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसका प्रदर्शन खराब होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। संकेत साफ हैं कि अगले तीन महीने नगरपालिका प्रशासन के लिए परीक्षा की घड़ी होंगे। अगर वसूली में सुधार नहीं हुआ तो न केवल कर्मचारियों के वेतन का संकट और गहराएगा, बल्कि प्रशासनिक अमले में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।

प्रत्येक निरीक्षक को वसूली का दिया लक्ष्य- शहर के 33 वार्डों में कार्यरत 17 सहायक राजस्व निरीक्षकों को अगले तीन महीनों में

वसूली का लक्ष्य सौंपा गया है। उन्होंने कहा वसूली में सुस्ती किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से बकायादारों से संपर्क करें और उन्हें बकाया राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहिक करें। सीएमओ ने कहा कि लंबे समय से एक ही वार्ड में पदस्थ निरीक्षकों के स्थानीय लोगों से बने व्यक्तिगत संबंधों के कारण राजस्व वसूली का काम प्रभावित हो रहा है। राजस्व वसूली की गति बढ़ाने के लिए सीएमओ ने सभी निरीक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 25 से 50 हजार रूपये की वसूली के निर्देश दिये है। जिसके बाद राजस्व निरीक्षकों में हडकंप मचा हुआ है।

आज 13 सितंबर की लोक अदालत से उम्मीदें- नगरपालिका में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है। जिसे लेकर बकायादारों को 15 दिन पहले ही नोटिस जारी कर राशि जमा करने के लिए कहा गया है। नगरपालिका के वरिष्ठ राजस्व अधिकारी ब्रजगोपाल परते ने बताया कि इस लोक अदालत से पहले बड़े से बड़े बकायादारों को नोटिस जारी किए है और उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर राजस्व जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। लोक अदालत के माध्यम से राजस्व वसूली में अच्छा सुधार की संभवना है। उल्लेखनीय है कि साल दर साल नपा की डिमांड बढ़ते जा रही है। पिछले कुछ सालों में नपा की डिमांड जहां 6 करोड़ हुआ करती थी, वहीं अब बढ़कर 11 करोड़ के लगभग पहुंच गई है।

अब तक 1 करोड़ 62 लाख की वसूली

नगरपालिका के राजस्व निरीक्षकों द्वारा विगत पांच माह में मात्र 1 करोड़ 62 लाख रूपये की ही वसूली की है। जो कुल वसूली का मात्र 13.92 प्रतिशत है। जबकि नगरपालिका की इस वर्ष की कुल डिमांड 11 करोड़ 63 लाख 93 हजार 135 रूपये की है, जबकि अभी तक मात्र 1 करोड़ 62 लाख 3 हजार 105 रूपये ही नपा वसूल कर पाई है। जिसमें सबसे कम वसूली दुकान/भवन भूमि किराया है। नपा को 84 लाख 87 हजार 81 रूपये वसूला है, जिसमें से नपा अभी तक मात्र 4 लाख 14 हजार 643 रूपये की वसूल सकी है, जो कि वसूला का मात्र 4.89 प्रतिशत है।

नगरपालिका की राजस्व वसूली की स्थिति

कर का नाम	कुल मांग	कुल वसूली
संपत्ति कर	40883440	8003513
समेकित कर	8526357	1020833
सामान्य जलकर	828124	133652
जल शुल्क	36383621	3734342
दुकान/भवन भूमि किराया	8487081	414643
शिक्षा उपकर	9906726	1345007.5
नगरीय विकास उपकर	11377786	1551114.5
योग	116393135	16203105

इनका कहना है -

कुछ ही दिनों पहले सहयक राजस्व अधिकारियों के वार्डो में फेरबदल किया है। राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए टारगेट दिया गया हैं, यदि कोई लापवाही करता हैं तो वेतन रोकने जैसी कार्रवाही की जायेगी। वैसे आज 13 सितंबर को लोक अदालत है, इसमें राजस्व वसूली में अच्छा सुधार होने की संभवना है।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ नगरपालिका बैतूल

न्यायालय विस्तार के लिए मांगी तहसील और एसडीएम कार्यालय की जमीन

बैतूल। जिला न्यायालय बैतूल में जगह की कमी अब गंभीर समस्या बन चुकी है। ब्रिटिश शासनकाल में बनी पुरानी अदालत की इमारत आज की न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रह गई है। बढ़ती अदालतों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों की संख्या ने परिसर को तंगहाल कर दिया है। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि पहले जहां मात्र 50 वकील कार्यरत थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 800 तक पहुंच चुकी है। इतने बड़े अधिवक्ता वर्ग और रोजाना आने वाले पक्षकारों के लिए न्यायालय परिसर में बैठने और कार्य करने की उचित व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की भी गंभीर समस्या है, जिससे आए दिन वकीलों और आमजनों को परेशानी उठानी पड़ती है। वर्तमान में न्यायालय परिसर में लगभग 16 अदालतें संचालित हो रही हैं, जिनमें कुटुंब न्यायालय और उपभोक्ता फोरम भी शामिल हैं। लेकिन जगह की कमी के कारण नई अदालतें शुरू नहीं हो पा रही हैं। इससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और न्यायाधीशों की पदस्थापना भी प्रभावित हो रही है। इन समस्याओं को देखते हुए जिला अभिभाषक संघ ने यह मुद्दा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संज्ञान में रखा। मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को पत्र लिखकर तहसील और एसडीएम कार्यालय से लगी जमीन न्यायालय परिसर को आवंटित करने का आग्रह किया है। यदि यह जमीन न्यायालय को मिल जाती है, तो मौजूदा दिक्कतों का काफी हद तक समाधान हो सकेगा।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति और एनीमिया अभियान के लिए शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण

बच्चों और महिलाओं को रोगमुक्त करने की तैयारी, 23 सितंबर को होगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

बैतूल। बच्चों और महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए भीमपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और एनीमिया मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया ताकि दवाओं का वितरण सटीक और प्रभावी रूप से हो सके। यह पहल बच्चों और महिलाओं को स्वस्थ भारत के निर्माण में सशक्त बनाएगी। 12 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर के मंगल भवन में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की कार्यशाला का

आयोजन किया गया। यह कार्यशाला एसडीएम भैंसदेही अजित मरावी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकासखंड भीमपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी भीमपुर एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भीमपुर उपस्थित रहे। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ दीपक निगवाल ने बताया कि 23 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थाओं शालाओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की दवा वितरित की जाएगी। इस दिन 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं 20 वर्ष से 49 वर्ष तक की सभी महिलाओं को एक गोली एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त मॉप-अप राउंड 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जिसमें छूटे हुए बच्चों एवं महिलाओं को दवा दी जाएगी। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को प्रति सप्ताह दो बार 1 मिलीग्राम आयरन सायरप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से पिलाया जाएगा। विद्यालयों में पढने वाले बच्चों को प्रति सप्ताह एक बार आयरन की गोली दी जाएगी। कार्यशाला में सभी शिक्षकों को इन दोनों अभियानों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया ताकि दवा वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि न हो और शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

सेवा पखवाड़ा अभियान में होंगी विविध जन कल्याणकारी गतिविधियां

कलेक्टर ने 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आयोजन के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश

बैतूल। प्रदेश में 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जल-भागीदारी, स्वच्छता, सेवा और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को व्यापक स्वरूप देना है। नागरिकों में स्वच्छता, सेवा और सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास तथा वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त करना है। अभियान के प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को समीक्षा कर संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिशा निर्देश दिए हैं। बताया गया कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ 17 सितंबर को किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम जयवंती हॉक्सर पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के साथ स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें हेल्थ स्क्रीनिंग, सिकल सेल एनीमिया की जांच, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता गतिविधियों भी आयोजित होंगी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नोडल प्राचार्य महाविद्यालय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान कैलेंडर अनुसार निबंध, वाद विवाद, चित्रकला , संगोष्ठी इत्यादि गतिविधियां आयोजित की जाएं। साथ ही जनसहयोग से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण और स्कूल परिसरों की साफ सफाई के कार्यक्रम भी कराएं।

निर्धारित तिथियों पर लगेगे हेल्थ कैंप और रक्तदान शिविर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सेवा पखवाड़ा अभियान की निर्धारित तिथियों में हेल्थ कैंप, रक्त दान शिविर, आयुष्मान शिविर, आंखों की जांच के लिए शिविर इत्यादि स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल एवं कल्याण विभाग को भी अभियान के तहत हॉकी, खो - खो, कबड्डी इत्यादि परम्परागत खेल गतिविधियों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को एक बगिया के नाम के तहत पौधरोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृहद स्तर पर पौध रोपण कर नमो वन बनाया जाएं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नगरीय प्रशासन और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को कैलेंडर बनाकर वार्डवार स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, वन मंडल अधिकारी, प्राचार्य महाविद्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सिविल सर्जन जिला अस्पताल, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत यह होगे कार्यक्रम

इसके अनुसार 17 सितम्बर को स्वच्छता रैली तथा शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छता अभियान, 18 को पौध-रोपण एवं पर्यावरण जागरूकता व्याख्यान, 19 को जैविक खेती के संबंध में जागरूकता रैली, किसानों के साथ चर्चा, 20 सितम्बर को सामाजिक कुरूतियों के प्रति जागरूकता व्याख्यान/नुक्कड नाटक, 21 को राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा श्रमदान एवं रैली, 22 को सामाजिक कुरूतियों के प्रति जागरूकता व्याख्यान/नुक्कड नाटक, 23 सितम्बर को ऊर्जा संरक्षण पर संवाद, 24 को स्थानीय लघु एवं कटीर उद्योगों के प्रति जागरूकता व्याख्यान, 25 को रक्तदान एवं रक्त परीक्षण शिविर, 26 को रक्त परीक्षण शिविर, 27 सितम्बर को सिकलसेल एनीमिया स्किनिंग शिविर में विद्यार्थियों की सहभागिता, 28 को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटस द्वारा श्रमदान एवं रैली, 29 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के साथ विद्यार्थियों की सहभागिता, 30 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के साथ विद्यार्थियों की सहभागिता, 1 अक्टूबर को पौध-रोपण एवं पर्यावरण जागरूकता एवं 2 अक्टूबर को सत्य एवं अहिंसा की शपथ/स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग/उत्पाद पर व्याख्यान एवं जनजागरण रैली का आयोजन किया जाए।

अधिकारियों ने किया फसलों का निरीक्षण, किसानों को दी सलाह

बैतूल। भैंसदेही विकासखंड के ग्राम सिवनी, रामघाटी, बडगाव, डूडिया नई, कौडिया, भीवकुण्ड में अधिकारियों ने फसलों का निरीक्षण किया। दरअसल इन गांवों से सूचना मिल रही थी कि सोयाबीन फसल पर अतिवर्षा, जड़ सडन, पीला रोग, तना मक्खी के प्रकोप से फसल को काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद कृषि विज्ञान केन्द बैतूल बाजार के पौध संरक्षण वैज्ञानिक आरडी बारपेटे एवं डॉ. आनंद बडोनिया उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा ग्राम सिवनी के कृषक अब्बादास एवं ग्राम बडगांव के संजय येवले एवं अन्य किसानों की सोयाबीन फसल का खेतों में पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि सोयाबीन फसल अतिवर्षा के कारण जड सडन और तना मक्खी के प्रकोप से फसल पीली दिखाई दे रही है। पीला रोग का प्रकोप नही देखा गया। सोयाबीन की फसल

प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के टोल फ्री नम्बर पर फोन करने की समझाइस दी गई। जिससे बीमित कृषको को बीमा योजना का लाभ मिल सकें। अधिकारियों ने किसानों को फसलों में कीट एवं व्याधियों के संक्रमण एवं उनके प्रबंधन की जानकारी दी। बताया कि सोयाबीन फसल में हरि अर्धकुण्डलक इल्ली, तम्बाकू की इल्ली, तना मक्खी आदि का प्रकोप प्राकृतिक रूप से कम होते हुए खत्म होगा। यह कीट अब चिंता का विषय नहीं है। फफूंदजन्य पर्णचित्ती रोग, जड़ सडन, तना सडन आदि आरंभिक अवस्था में है। सभी रोगों का प्रकोप आगामी समय में तीव्र होंगे एवं फसल को व्यापक क्षति पहुंचाएंगे। इन रोगों के प्रभावी प्रबंधन के लिए टेबूकोनाजोल सल्फर 25 ग्राम या पायरोक्लर ट्रोबिनफ़्लक्सा पायरोक्जाइड 0.75 मि.ली. प्रति लीटर पानी का छिडक़ाव करें। खरीफ की दूसरी प्रमुख फसल मक्के में फॉल आगी वर्म (पत्तियों में छिद्र एवं तने के अंदर सुरग) के साथ जीवाणुजन्य बेक्टीरियल स्टॉक रॉट, फफूंदजन्य शीथ ब्लाइट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। आगामी दिनों में इन रोगों का प्रकोप तेजी से बढेगा। नत्रजन युक्त उर्वरक के असतुलित एवं अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने से ये कीट एवं रोग तेजी से फैलते हैं। प्रबंधन उपाय में नत्रजन युक्त उर्वरक (यूरिया) के प्रयोग को स्थगित करें। रोगी पौधों को खेत से बाहर भी निकालें। फॉल आर्मी वर्म के प्रबंधन हेतु इमामेक्टीन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर या फ्लूबेंडामाइड 0.5 मिली. प्रति लीटर का छि?काव करें। बेक्टीरियल स्टॉक रॉट के प्रबंधन हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर, स्ट्रेप्टोसाइक्लीन 0.2 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर आक्सीक्लोराइड एग्रीमायसीन 25 ग्राम प्रति लीटर का छिडकाव करें।

एक माह में सभी कार्य पूर्ण करें : कलेक्टर

सांसद, विधायकनिधि के निर्माण कार्यों की समीक्षा

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने गुरूवार को जिले में सांसदनिधि और विधायकनिधि के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने निर्माण ऐजेन्सियों को निर्देशित किया है कि आगामी एक माह में शेष सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता को ध्यानगत रखते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि दशहरा के उपरांत पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं पाए गए तो संबंधित ऐजेन्सी के साथ-साथ मानिटरिंग अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जो भी निर्माण कार्य पूर्ण कराए जा रहे है खासकर सांसदनिधि के कार्यों की अद्यतन जानकारी ई-साक्षी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना है ताकि भारत सरकार निर्माण कार्य की स्थिति से अवगत हो सकें। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि जनपदो के कार्यो की समीक्षा बैठक में सांसद व विधायक निधि के निर्माण कार्यों की भी पृथक से समीक्षा की जाए। उसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि इसी गांव में एक ही निर्माण कार्य के लिए अन्य किसी मद की राशि ना जारी हो खासकर सांसद निधि, विधायक निधि और बस्ती विकास निधि के माध्यम से संपादित किए जाने वाले कार्यों में एकरूपता ना हो का विशेष ध्यान रखा जाए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसे निर्माण कार्य जिनके लिए निजी ऐजेन्सियां नियुक्त की गई है उनकी पृथक से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने उपरोक्त बैठक के दौरान सभी जनपदो के सीईओ और निकायो के अधिकारियों को आगामी तिथियों में शुरू होने वाले अभियानो के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर रणनीति तय कर शत प्रतिशत अभियान की निहित बिन्दुओं की प्राप्ति सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि नेशनल हाईवे सड़को के मार्गो पर पशुओं का विचरण ना हो खासकर रात्रि में पशु सडको पर बैठे ना हो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए और संबंधित ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र की गौशाला में ऐसे सभी पशुओं को पहुंचाने की व्यवस्था क्रियान्वित की जाए। गौशाला में आने के उपरांत पशु स्वामियों को शुल्क जमा करने पर ही पशु प्रदाय किए जाएं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रो की सीमा अन्दर गौवंश के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए निकायो के अधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित सांसद निधि योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यो की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार प्रस्तुत की गई जिसमें स्वीकृत कार्य एवं प्रगतिरत व अप्रारंभ कार्यो से अवगत कराया गया हैं इसी प्रकार विधायक निधि योजना के तहत स्वीकृत किए गए कार्यो की अद्यतन जानकारियां संबंधित निर्माण ऐजेन्सी द्वारा विधानसभावार, कार्यवार प्रस्तुत की गई है। सांसद निधि के तहत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कुल 258 कार्य स्वीकृत किए गए है जिनमें से 201 कार्य पूर्ण कराए गए है शेष कार्य प्रगतिरत हैं। इसी प्रकार पूर्व उल्लेखित वित्तीय वर्षो में विधायक निधि के कुल 1872 कार्य स्वीकृत किए गए है जिसमें से 1739 कार्य पूर्ण कराए जा चुके है शेष अन्य कार्यो की अद्यतन स्थितियां भी सांझा की गई है। उपरोक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोड़िया, अतिरिक्त जिपं सीईओ श्री पंकज जैन के अलावा निर्माण कार्यो को संपादित कराने वाले विभागो के कार्यपालन यंत्री तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी श्री सेवाराम रैकवार, निकायो के अधिकारी, समेत अन्य विभागो के अधिकारी मौजूद रहें जबकि जनपदों के सीईओ व इंजीनियरो से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संवाद किया गया।

मुख्यमंत्री ने रतलाम के सैलाना तहसील के ग्राम करिया के खेतों में पहुंचकर पीड़ित किसानों को ढांढस बंधाया।

अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान विजेताओं को मिलेगा 50,000 रुपये तक का पुरस्कार

भोपाल। भारतीय डाक विभाग द्वारा ''अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान'' वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 08.09.2025 से 08.12.2025 तक किया जा रहा है। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय ''मेरे आदर्श को पत्र /Letter to my Role Model' निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए खुली है। इसके अंतर्गत दो श्रेणियाँ (18 वर्ष तक एवं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) तथा प्रत्येक श्रेणी में दो उप-श्रेणियाँ - (i) अंतर्देशीय पत्र (अधिकतम 500 शब्द) और (ii) लिफाफा (अधिकतम 1000 शब्द) निर्धारित की गई हैं। प्रतिभागियों को हस्तलिखित पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखकर संबंधित प्रवर अधीक्षक डाकघर / अधीक्षक डाकघर कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट अथवा हाथों-हाथ जमा करना होगा। साथ ही प्रतिभागी को दिनांक 01.09.2025 को अपनी आयु 18 वर्ष से कम अथवा अधिक होने संबंधी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

संक्षिप्त समाचार

आर्थिक मदद जारी

विदिशा (निप्र)। विदिशा एसडीएम के द्वारा एक प्रकरण में आर्थिक सहायता के आदेश जारी कर दिए गए है। नायब तहसीलदार के पालन प्रतिवेदन पर विदिशा एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा ने राहुल पिता तुलाराम की मृत्यु बेतवा नदी में डूबने से हो जाने के कारण मृतक की पत्नि वंदना मालवीय को आरबीसी 6(4) प्रावधानो के तहत चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है।

स्वयंसेवकों को लार्वा सर्वे एवं व्यवहार परिवर्तन का प्रशिक्षण दिया गया

विदिशा (निप्र)। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा फैमिली हेल्थ इंडिया के तत्वाधान में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सहयोग व जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर टीकाराम शर्मा के मार्गदर्शन में चल रही एम्बेड परियोजना के अंतर्गत जिला मलेरिया कार्यालय में मलेरिया विभाग की टीम द्वारा स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन एवं लार्वा सर्वे का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देते हुए मलेरिया निरीक्षक श्री विजय विश्वकर्मा ने बताया कि समुदाय को डेंगू मलेरिया एवं मच्छर से होने वाले अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से फैलती है, साथ ही उन्होंने डेंगू के लक्षण जैसे कि बुखार सिर दर्द मांसपेशियों में दर्द त्वचा पर लाल चकते बनना एवं लार्वा की जांच करने व लार्वा को नष्ट करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की चूँकि विदिशा जिला विगत वर्षो में डेंगू से अधिक प्रभावित रहा है अतः इस जागरूकता अभियान के माध्यम से, स्वयंसेवक लोगों को डेंगू से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। शहर के उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जिनमें विगत वर्षों में डेंगू का अधिक प्रकोप रहा है। एम्बेड के कुल 41 स्वयंसेवकों को आज प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण में एम्बेड टीम के साथ मलेरिया विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

ई-स्कूटी योजना के लिए छात्र अनिल ने सीएम को दिया धन्यवाद

विदिशा (निप्र)। ई-स्कूटी योजना के लिए विदिशा के छात्र श्री अनिल अहिरवार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री बालक-बालिका ई-स्कूटी योजना अंतर्गत विदिशा के छात्र श्री अनिल अहिरवार लाभान्वित हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम से सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि अंतरित की है, जिसमें विदिशा के सांदीपनि विद्यालय बरईपुरा के छात्र श्री अनिल अहिरवार भी शामिल हैं। योजना अंतर्गत ई-स्कूटी के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि मिलने पर छात्र श्री अनिल अहिरवार ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा मैधावी छात्र-छात्राओं के लिए चलाई जा रही ई-स्कूटी योजना प्रशंसनीय है। इस योजना का लाभ मिलने से हम छात्रों को आने-जाने में सहूलियत होगी साथ ही उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों के लिए प्रारंभ की गई इस योजना से लाभ मिलने से हम छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ता है। सांदीपनी स्कूल बरईपुरा विदिशा में पढ़ने वाले छात्र श्री अनिल अहिरवार ने बतिया कि वह आमखेड़ा कालू गांव के रहने वाले हैं।

रीवा मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

संजय गांधी हॉस्पिटल में डक्ट कूलिंग सिस्टम का किया लोकार्पण

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने संजय गांधी अस्पताल रीवा में डक्ट कूलिंग सिस्टम और 17 व्हील चेयर का लोकार्पण किया। डक्ट कूलिंग सिस्टम से दो वार्डों में रोगियों और उनके परिजनों को शीतल हवा मिलेगी। इसका निर्माण आइनॉक्स कंपनी द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा तेजी से मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर है। उपचार के लिए नागपुर जाने वाले रोगियों की संख्या में कमी आई है। कुछ ही महीनों में कैंसर यूनिट का निर्माण पूरा होते ही रीवा में दो सौ बेड का कैंसर अस्पताल शुरू हो जाएगा। इसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से लीनेक मशीन लगाई जा रही है। इस अस्पताल में कैंसर के उपचार की आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध रहेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में सुधार तथा नई व्यवस्थाओं के लिए 321 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सर्जरी विभाग में सिंगरौली की एनसीएल कंपनी द्वारा दी गई 6 करोड़ रुपए की सहयोग राशि से आधुनिक मशीन लगाई जा रही है। यहाँ के डॉक्टर बहुत योग्य हैं। डॉक्टर और चिकित्साकर्मी अस्पतालों की आत्मा हैं। उन्होंने कहा कि रोगियों का अच्छा उपचार करने के साथ उनसे मृदु व्यवहार भी करें। डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से रोगी का आधा रोग ठीक हो जाता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आईनॉक्स कंपनी ने कोरोना संकट के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति करके सराहनीय कार्य किया। कंपनी ने संजय गांधी अस्पताल के दो वार्डों में कूलिंग सिस्टम लगाया है।

आईनॉक्स कंपनी के प्रतिनिधि श्री अतुल कुमार ने कहा कि कंपनी प्रतिदिन 4500 टन ऑक्सीजन का निर्माण कर रही है। कोरोना काल में प्रतिदिन 40 टैंकर ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश को की जा रही थी। जनकल्याण के लिए कंपनी सदैव सहयोग करेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय, मेडिसिन विभाग के डॉ पीके बघेल, संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ राहुल मिश्रा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पीएमश्री एमएलबी स्कूल में ई-स्कूटी योजना कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ

विधायक श्री टंडन हुए कार्यक्रम में शामिल

विदिशा (निप्र)। पीएम श्री महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्य प्रदेश शासन की ई स्कूटी योजना के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के लाइव प्रसारण को जिसे कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों व स्कूली छात्राओं के द्वारा देखा सुना गया। विधायक श्री मुकेश टंडन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित पीएम श्री गर्ल्स स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय की सर्वोच्च अंक प्राप्त सुहानी राठौर को स्कूटी की राशि प्राप्त हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक श्री मुकेश टंडन जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्यप्रदेश शासन बेटियों के एवं शिक्षा अर्जित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और यह गौरव की बात है की मध्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक टॉपर बच्चों को स्कूटी प्रदाय की जा रही है उन्होंने छात्राओं को आगे बढ़कर अच्छे से पढ़ाई करने और संस्कारवान बने के लिए अभिप्रेरित किया।

स्वागत उद्बोधन विद्यालय की प्राचार्य डॉ दीप्ति शुक्ला के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती आभा पाराशर के द्वारा किया गया एवं विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षा शिक्षिकाएं मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा विदिशा जिले के सभी स्कूलों में उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने व सुनने की प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे।

विधायक ने मेधावी छात्र को दी शुभकामनाएं

विधायक श्री मुकेश टंडन इसके पहले विदिशा के बरईपुरा स्थित सांदीपनि विद्यालय में आयोजित ई-स्कूटी वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए उन्होंने यहां भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों की हौसला अफजाई कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हेलमेट पहन कर विद्यार्थियों को दिया सुरक्षा का संदेश

स्कूल के टॉपर्स स्कूटी चलाते वक्त यातायात सुरक्षा नियमों का रखें ध्यान : स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री सिंह

भोपाल (नप्र)। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने आह्वान किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूटी वितरण से लाभान्वित टॉपर्स स्कूटी चलाते वक्त यातायात सुरक्षा नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें। उन्होंने कहा कि 11 सितम्बर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में हेलमेट पहन कर स्कूटी पर सवारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हेलमेट पहन कर विद्यार्थी को यह संदेश भी दिया कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है।

यातायात नियमों का रखें ख्याल-स्कूल एवं परिवहन मंत्री श्री सिंह ने हितग्राही विद्यार्थियों से सुरक्षा के लिये यातायात नियमों का पालन करने का आहवान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्कूटी चलाते वक्त हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और पीछे बैठने वालो को भी दोनों हेलमेट पहनें के लिये कहें। ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन का पालन जरूर करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, मोबाइल का उपयोग दुर्घटना का कारण बनता है। सड़?क पर मुड़ने से पहले इंडिकेटर अवश्य दें और हॉर्न का अनावश्यक

प्रयोग न करें। गलत दिशा में न चलें और ओवरटेक से बचें। वाहन की नियमित जाँच करें। ब्रेकलाइट, टायर और अन्य उपकरण सही हालत में रखें। दो पहिया वाहनों पर दो से ज्यादा लोग न बैठें। परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग ने 16 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र में 50 सीसी से कम इंजन वाली गेयरलेस वाहन के लिये, 16 साल की उम्र में लर्नर लायसेंस ओर 18 साल पूरे होने पर गियर वाले लाइट मोटर व्हीकल के लिये स्थायी ड्रायविंग लायसेंस दिये जाने का प्रावधान है। लर्नर लायसेंस जारी होने के 30 दिन बाद 180 दिन के भीतर ड्रायविंग टेस्ट देना अनिवार्य किया गया है।

पिछले 3 वर्षों में 23 हजार 454 टॉपर्स को दी गई स्कूटी

प्रदेश में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार ने 3 वर्ष पहले निःशुल्क स्कूटी प्रदाय योजना शुरू की थी। इस योजना में अब तक सरकारी हायर सेकेण्डरी स्कूल में 23 हजार 454 टॉपर विद्यार्थियों को 246 करोड़ 58 लाख रूपये की राशि व्यय कर स्कूटी प्रदान की गई है। टॉपर्स द्वारा चयन की गई पेट्रोल स्कूटी पर 90 हजार और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चयन करने पर एक लाख 20 हजार रूपये की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। इस राशि में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और हेलमेट की सुविधा भी शामिल है।

निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस सभागार रीवा में विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बसामन मामा गौ वन्य विहार, पेयजल की आपूर्ति तथा जल संरक्षण के कार्य तत्परता से पूरा कराएं। हिनौती गौधाम में भी स्वीकृत निर्माण कार्य पूरा कराकर निराश्रित गौवंश को रखने की व्यवस्था करें। बाउन्ड्रीवॉल और सड़क निर्माण का कार्य तत्परता से पूरा कराएं। उन्होंने चिरहुलानाथ मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों तथा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

प्रतिभाशाली युवा ही राष्ट्र की सच्ची पूंजी है : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा ही देश की सच्ची पूंजी हैं। परिश्रम और लगन से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। मेरिट में स्थान प्राप्त करके सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों की सफलता के पीछे उनकी प्रतिभा और परिश्रम की कठिन साधना है। विद्यार्थी संस्कारयुक्त शिक्षा और ऊंचे लक्ष्य प्राप्त कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं। जो विद्यार्थी मेरिट सूची में स्थान नहीं बना सके वे पुनः अधिक मेहनत के साथ प्रयास करें। असफलता से मिली सीख ही हमें सफलता की राह दिखाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा तभी सम्पूर्ण होगी जब उसमें सांस्कृतिक मूल्यों और अच्छे संस्कारों का समावेश हो।उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए स्वामी विवेकानंद का जीवन सबसे प्रेरक है।

जबलपुर में बीएसएनएल की चार मंजिला इमारत गिरी

एक शख्स घायल; पुलिस-प्रशासन और नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर में शुक्रवार की शाम को विजय नगर स्थित पीएनटी कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हो गया। बीएसएनएल की पुरानी चार मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह इमारत कई साल पुरानी थी और अचानक ही भरभराकर गिर गई। बिल्डिंग गिरने की जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी इमारत को देखकर लोग हैरान रह गए और तुरंत मदद के लिए आगे आए।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची विजय नगर थाना पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड

की टीम भी मौके पर पहुंची हैं। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों ने बताया- पुरानी और जर्जर हो चुकी थी इमारत

घायल शख्स बिल्डिंग गिरने के समय वहां क्या कर रहा था। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि, शुरुआती चर्चाओं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से यह सामने आया है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी होने के कारण कमजोर हो चुकी थी और संभवतः इसी वजह से यह ढह गई। जिला प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया

एसडीएम पंकज मिश्रा ने बताया कि इस बिल्डिंग में कोई परिवार नहीं रहता था। हादसे में देवेंद्र रैकवार नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हंगामे के चलते रद्द हुआ शिवराज का किसान संवाद कार्यक्रम

सतना में कांग्रेस और पुलिस की झड़प; कांग्रेसी बोले- सरकार जनता की आवाज से डरी

सतना (नप्र)। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले पुलिस

और कांग्रेसियों की झड़प हो गई। कांग्रेस ने खाद संकट को लेकर शिवराज के घेराव और काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था। हंगामा बढ़ने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।

घटना गुरुवार देर शाम की है। शिवराज दोपहर 3 बजे जिले के कुंदहरी में किसान संवाद में शामिल होने वाले थे। ऐनवक्त पर कार्यक्रम कैंसिल होने को लेकर कांग्रेस नेत्री डॉ. रश्मि पटेल ने कहा, सरकार जनता की आवाज से डर गई है, इसलिए मंत्री का कार्यक्रम बदल दिया गया।

कांग्रेस ने किया था घेराव का ऐलान-नागौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं डॉ. रश्मि पटेल ने अपने समर्थकों के साथ बिहटा गांव में केंद्रीय मंत्री के विरोध की तैयारी की थी। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। सरकार इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। उचेहरा थाने और अन्य थानों से पुलिस बल बुलाकर गांव में तैनात कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता हाईवे की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस हुई। इसके बाद दोनों में झड़प हो गई। कुछ कार्यकर्ता हाईवे पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी।

उपराष्ट्रपति से मिले सीएम डॉ. मोहन यादव

दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री मुरुगन और राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भी की मुलाकात

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार शाम को दिल्ली पहुंचे। सीएम ने यहां नव निर्वाचित उप राष्ट्रपति डॉ. सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर बधाई दी। बता दें कि मंगलवार को उप राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। जिसमें एनडीए के उम्मीदवार डॉ. सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की थी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली स्थित मप्र भवन में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन और मप्र के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भी मुलाकात की।

हाईकोर्ट ने अक्षय-अरशद वारसी समेत 8 को भेजा नोटिस

जॉली एलएलबी 3 के 'भाई वकील' गाने पर आपत्ति, 17 सितंबर को होगी सुनवाई

जबलपुर (नप्र)। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी जॉली एलएलबी 3, 19 सितंबर को रिलीज होगी, जिसमें

अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिकाओं में हैं। लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में आ गई है। 'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है' गाने पर आपत्ति जताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दोनों अभिनेताओं समेत 8 लोगों को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब मांगा है। यह याचिका अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने दायर की है। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी पहली बार कोर्टरूम में एक-दूसरे के खिलाफ दलीलें देते नजर आएंगे।

फिक्र न कर तेरा भाई वकील है

अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की याचिका में कहा गया कि फिल्म में गले में बैंड लगाकर और गाउन पहनकर डांस किया गया है। साथ ही गाने में 'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है' जैसे बोल और कोर्टरूम में डांस का दृश्य दिखाया गया है, जो वकालत पेशे और न्यायपालिका की गरिमा का अपमान है।

उज्जैन में कांग्रेस की किसान अधिकार यात्रा

जीतू पटवारी ने कहा- सड़कों पर गोमाता दिखी तो घेरकर कलेक्ट्रेट ले जाएंगे

उज्जैन (नप्र)। एमपी कांग्रेस ने उज्जैन में शुक्रवार को किसान अधिकार यात्रा का आयोजन किया। इससे पहले चिमनगंज मंडी परिसर में सभा आयोजित हुई। सभा में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला।

सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को चुनौती दी। पटवारी ने कहा- कांग्रेस पार्टी आने वाले 15 दिनों में अभियान चला रही है। जिस शहर में जहां भी गोमाता सड़क पर नजर आएंगी वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें घेरकर कलेक्टर कार्यालय लेकर जाएंगे। यहां सारे कांग्रेसजन गोमाता की सेवा करेंगे। पटवारी ने कहा कि सीएम ने शहर में पूरी तरह शराबबंदी की बात कही थी। लेकिन, आज शहर की हर गली में अवैध रूप से शराब मिल रही है।

सभा के बाद कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च

सभा के बाद कृषि उपज मंडी गेट से किसान न्याय यात्रा शुरू हुई। जैसे ही यात्रा चामुंडा माता पहुंची, यहां एडीएम अतेंद्र सिंह गुर्जर को ज्ञापन दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट, जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेता और विधायक महाकाल दर्शन के लिए रवाना हो गए। टावर चौक पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

गुना विधायक पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग

सभा के दौरान पीसीसी चीफ पटवारी ने गुना क्षेत्र के विधायक द्वारा दिए गए बयान पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने निर्वाचन आयोग में अपनी मर्जी से नियुक्ति की जिसके कारण देश का लोकतंत्र खतरे में है।

पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चोरी से वोट डलवाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि शहर में कहीं भी शराब की दुकान नहीं होगी। लेकिन, शहर की हर गली में अवैध रूप से शराब मिल रही है। लैंड पुलिंग मामले में मुख्यमंत्री ने डंडे के जोर पर किसानों की जमीन लेने का प्रयास किया है।

पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को चुनौती देते हुए कहा- कांग्रेस पार्टी आने वाले 15 दिनों में अभियान चला रही है। जिसमें जिस शहर में जहां भी गोमाता सड़क पर मिलेगी। वहां से गोमाता को घेरकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय लेकर जाएंगे। यहां सारे कांग्रेसजन गाय माता की सेवा करेंगे।

आदिवासी, दलित और किसानों का हो रहा शोषण

किसान न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा- निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। लेकिन इसमें भारी कमी है। वोट चोरी हो रही है।11 साल से जो शासन चला रहे उन्हें कोई परवाह नहीं, एमपी में आदिवासी, दलित सबका शोषण हो रहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश की जनता को वोट चोरी के बारे में दिखाया। आज खाद, बीज, बिजली पानी किसी भी बात की चिंता सरकार को नहीं है। मैं आश्वस्त करता हूं किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जाती जनगणना, जीएसटी जैसे फैसले वापस लिए जाएगा।

कार्यकर्ताओं के साथ बैठे दिखे दिग्विजय सिंह

सभा के दौरान दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहली पंक्ति में बैठे हैं। वहीं बाकी वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। मंच पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और गुना कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह सहित कई नेता नजर आए।

सभा में 25 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था

कांग्रेस की सभा के लिए 90 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा मंच बनाया गया था। इसके साथ ही 190 बाय 550 फीट का डोम लगाया गया था। जिसमें 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी।

देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, ऐप लॉन्च होगा

एमपी में फरवरी से डेढ़ लाख कर्मचारी काम में जुटेंगे, प्रदेश के 3 जिलों में प्री टेस्ट भी

भोपाल (नप्र)। साल 2026-27 में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना निदेशालय इसके लिए एप लॉन्च करेगा। यह एप एंड्राइड-आईफोन दोनों के लिए होगा। परिवार का मुखिया इसमें अपने घर-परिवार की जानकारी खुद भर सकेगा।

एप पर डिटेल भरने के बाद जनगणना अधिकारी घर जाकर जानकारी क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद उसे डिजिटल फॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। जनगणना में शामिल कर्मचारी को 150-175 मकानों की जिम्मेदारी होगी। जनगणना शुरू होने से पहले प्रदेश के 3 जिलों में इसका प्री टेस्ट होगा। गड़बड़ी रोकने प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसम्बर 2025 की स्थिति में फ्रीज करने का फैसला लिया गया है।

2 चरणों में होगी जनगणना

जनगणना 2026 और 2027 में दो चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकानों की गिनती की जाएगी। दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें लोगों की जनसंख्या, जाति और बाकी जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी।

इसके लिए 16 जून 2024 को सरकारी अधिसूचना जारी की गई है। यह आजादी के बाद भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी।

34 लाख कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग

इतने बड़े काम के लिए सरकार ने देशभर में करीब 34 लाख लोगों को नियुक्त किया है। इन कर्मचारियों को तीन स्तरों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले राष्ट्रीय ट्रेनर, फिर मास्टर ट्रेनर और आखिर में फील्ड ट्रेनर इन्हें तैयार करेंगे। हर गांव और शहर को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा और हर हिस्से के लिए एक कर्मचारी जिम्मेदार होगा। इससे कोई भी घर या व्यक्ति गिनती से न छूटे।

फरवरी 2026 तक डेढ़ लाख कर्मचारियों की तैनाती होगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। जनगणना निदेशालय ने राज्य सरकार को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज करने का पत्र भेजा है। इसके बाद गृह विभाग ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं।

फरवरी 2026 में पहले राउंड में पूरे प्रदेश में डेढ़ लाख कर्मचारियों की तैनाती होगी। 20 दिन में डिजिटल जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद आंकड़ों को मिलाकर जनगणना आयुक्त को भेजा जाएगा। इस बार पूरी जनगणना डिजिटली होगी।

'यूका' का कचरा जलवाने, स्वास्थ्य शिविर लगाने में दीपक सिंह की भूमिका बेजोड़

धार के इमामबाड़े का मामला सुलझाया, उपलब्धियों के खाते में कई मामले

इंदौर। अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इंदौर संभाग के कमिश्नर के रूप में दीपक सिंह का करीब डेढ़ साल का कार्यकाल अच्छे प्रशासक और बेहतर प्रशासनिक कार्यशैली के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इंदौर संभाग का उनको दीर्घ अनुभव रहा और उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कार्यशैली से सबको प्रभावित किया।

खरगोन जिला पंचायत सीईओ, धार जिला पंचायत सीईओ, इंदौर आईडीए सीईओ, धार कलेक्टर, बुरहानपुर कलेक्टर इंदौर संभाग आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल में कई मिसाल पेश की। कुशल प्रशासक के रूप में दीपक सिंह का कार्यकाल और भूमिका को न केवल प्रशासनिक महकमा बल्कि इंदौर संभाग के नागरिक भी सदैव याद रखेंगे। बतौर कमिश्नर दीपक सिंह ने पीथमपुर के कचरा निपटान में जन आक्रोश को थामने के लिए लगातार बैठकें की और जनता से संवाद स्थापित किया। जब सरकार एवं प्रशासन से आम जनता का भरोसा उठ रहा था तब दीपक सिंह ने कहा कि मैं वहीं बैठूंगा, जब तक कचरा जलेगा। इस एक वाक्य ने आमजन में भरोसा पैदा किया और लोग भी मान गए कि कचरा निपटान को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें दम नहीं। उस दिन रामकी के गेट पर बैठे और इस देश और प्रदेश व्यापी समस्या का मानो चुटकियों में निपटारा कर दिया।

धार में कलेक्टर, जिपं सीईओ रहने के कारण नर्मदा पट्टी का

असंतोष भी उन्होंने दूर करने में प्रभावी भूमिका निभाई। मेधा पाटकर जब भूख हड़ताल पर बैठी तब बातचीत का रास्ता निकालने के लिए दीपक सिंह ने दिल्ली और मुम्बई के सूत्र निकाले। मेधा पाटकर को भूख हड़ताल से उठाकर और उन्हें मनाने में सफलता हासिल कर दीपक सिंह ने न केवल सरकार को संकट में आने से बचाया बल्कि सरकार और सरकार के मुखिया के सामने अपनी बेहतर छवि भी पेश की।

धार जैसे संवेदनशील शहर के इमामबाड़े मामले को भी बड़ी चतुराई से निपटाया। जबकि, एक समय तो यह लगा था कि इमामबाड़ा मामला साम्प्रदायिक विवाद न खड़ा कर दे। किंतु, दीपक सिंह ने उसे भी कानूनी जामा पहनाकर जिस तरह से हैंडल किया वह भी कुशल प्रशासनिक दक्षता का बेजोड़ उदाहरण है। धार जैसे संवेदनशील शहर में दोनों संप्रदायों बगैर वैमनस्यता लाए इस मामले को अच्छे से समाप्त करना उनके प्रशासनिक करियर के लिहाज से बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

इंदौर संभाग में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के दौरे भी निर्विघ्न सम्पन्न करवाए। इसी प्रकार इंदौर संभाग में झांकी के विसर्जन जुलूस के पूर्व जिला प्रशासन के अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन तथा समर्थन देकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम निपटाए। यह भी दीपक सिंह जी के कुशल प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। बुरहानपुर में साम्प्रदायिक हिंसा को तत्काल रोकने में भी दीपक सिंह जी की भूमिका प्रभावी रही।

हैदरी दल का मुख्य संचालक छिंदवाड़ा से अरेस्ट

बरेली (नप्र)। बरेली पुलिस ने हैदरी दल के मुख्य संचालक को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से अरेस्ट कर लिया। वह इंस्टाग्राम पर दो अकाउंट्स और यूट्यूब पर एक चैनल चला रहा था। तीनों ही जगह वह फेक न्यूज और धर्म विशेष के खिलाफ पोस्ट करता था।

आरोपी का मकसद, देशभर के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना और समाज में नफरत फैलाना था। पुलिस को पूछताछ में कई इनपुट मिले हैं। अब वह इस दल से जुड़े लोगों की अरेस्टिंग करने की तैयारी में है।

हैदरी दल यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है

गुरुवार को एसपी सिटी मानुष पारीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अकबर खान मूल रूप से यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। मगर उसका परिवार छिंदवाड़ा में बस गया है। उसे 11 सितंबर को अरेस्ट किया गया। अकबर ने इंस्टाग्राम पर 2 अकाउंट बनाए। जिनके नाम, टीम हैदरी दल, हैदरी दल ऑफिशियल हैं। इसके अलावा वह यूट्यब पर राष्ट्रीय टीवी नाम से चैनल ऑपरेट कर रहा था। कई वॉट्सऐप ग्रुप भी चला रहा था।

हिंदुओं के प्रति समाज में नफरत फैलाना मकसद था, मुसलमानों को भड़का रहा था

पुलिस के मुताबिक, अकबर ने पूछताछ में बताया कि मेरा मकसद मुसलमानों में गलतफहमी पैदा करना और उन्हें भड़काना है। हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करना है। इसके लिए मैंने कई फर्जी फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इन पोस्टों में मैं दूसरे देशों यहां अन्य जगहों के वीडियो को फर्जी तरीके से पोस्ट करता था।

हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना था उद्देश्य

मैंने तमाम ऐसे पोस्ट किए कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। मस्जिदों में बुलडोजर चल रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के भगवा लव ट्रैप में फंसा रहे हैं। मगर ऐसा कुछ होता नहीं था।

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया- पुलिस अकबर की कॉल डिटेल और चैट हिस्ट्री खंगाल रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किन-किन लोगों से जुड़ा था। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि उसके अकाउंट्स को किन शहरों से सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा था।

ग्वालियर में पत्नी के चेहरे को गोलियों से भूना

सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस पर भी पिस्टल तानी

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में शुक्रवार दोपहर को एक महिला को गोलियों से भून दिया गया। घटना रूप

अरविंद परिहार, आरोपी

सिंह स्टेडियम के सामने की है। यहां बदमाश ने उसे रोका और उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर भी पिस्टल तान दी।

पुलिस ने उसे काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा। उसकी पिटाई भी की। फिर उसे उठाकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि महिला को 4-5 गोली लगी है। उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पता चला कि पीड़ित महिला और आरोपी पति-पत्नी है। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था।

डायबिटीज में सुबह ज्यादा पानी और शीर्षासन बना रहा अंधा

100 रोगियों में से 10 को ग्लूकोमा रोग; आज ग्लौकोताल में आएंगे 600 विशेषज्ञ

भोपाल (नप्र)। क्या आपके चश्मे का नंबर बार-बार बदल रहा है, आंखों में खुजली और आंसू आने के साथ सिरदर्द भी रहता है? यह लक्षण कालापानी यानी ग्लूकोमा के हो सकते हैं। गुरुवार को भोपाल में आयोजित ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात विशेषज्ञों ने कही। इस दौरान जानकारी दी गई कि शुक्रवार से शनिवार तक भोपाल में सोसाइटी का ग्लौकोताल आयोजन होटल ताज में हो रहा है, जिसमें देश और दुनिया के 600 विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सम्मेलन की ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. विनीता रामनानी ने कहा कि यह साइलेंट रोग है। हमारे पास 75 प्रतिशत वे मरीज आते हैं, जिनमें एक आंख की रोशनी बिल्कुल जा चुकी होती है। बिना लक्षण वाले इस रोग का खतरा मधुमेह रोगियों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। हर 100 डायबिटिक मरीजों में से 10 से 11 में यह रोग मिलता है। ऐसे लोग यदि सुबह एक साथ ज्यादा पानी (करीब एक लीटर) पीते हैं, तो यह रोग तेजी से बढ़ता है। ऐसा ही लंबे समय तक शीर्षासन करने से होता है। यह दोनों बातें उन पर लागू होती हैं जिनमें इस रोग का रिस्क हो। चिंता की बात यह है कि ग्लूकोमा रोग की शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते। ऐसे में यह गतिविधियां व्यक्ति खुद को स्वस्थ रखने के लिए करता है, लेकिन इसका उल्टा असर आंखों पर पड़ता है, जो उसे तेजी से अंधा बना रहा होता है। यह रोग इसलिए भी घातक है क्योंकि इसमें आंखों की रोशनी दोबारा लौटाई नहीं जा सकती।

ग्लूकोमा की समय से पहचान ही एक रास्ता-ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉ. सत्यन पार्थसारथी ने कहा कि इस रोग से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि समय पर जांच कराई जाए। यदि व्यक्ति की आयु 40 साल से अधिक है, डायबिटीज है, चश्मे का नंबर बदल रहा हो या परिवार में किसी को यह बीमारी हुई हो, तो जल्द से जल्द ग्लूकोमा का टेस्ट कराना चाहिए। यह जांच प्राइवेट से लेकर सरकारी सेटअप में उपलब्ध है।

ग्लूकोमा के इलाज में नजर आते हैं साइड इफेक्ट्स-

सोसाइटी के वर्किंग चेयरमैन डॉ. गजेंद्र चावला ने कहा कि ग्लूकोमा यदि समय पर पहचान लिया जाए, तो भी मरीज के लिए इलाज जारी रखना चुनौती है। बिना लक्षण वाले इस रोग में मरीज को विश्वास दिलाना मुश्किल होता है कि वह बीमार है। ऊपर से इलाज में दी जाने वाली ड्रॉप और दवाओं से आंखें लाल होना और खुजली जैसे लक्षण उभरते हैं। ऐसे में मरीज को लगता है कि उसका गलत इलाज हो रहा है और वह बीच में इलाज छोड़ देता है। इसके बाद दोबारा तब आता है, जब एक आंख की रोशनी पूरी तरह जा चुकी होती है।

हमारे बीच कई लोग अनजान-जॉइंट सेक्रेटरी डॉ. मधुलिका ने बताया कि इस रोग के साथ कई लोग जी रहे हैं। करीब 70 से 75 प्रतिशत ऐसे मरीज हैं, जिनमें बीमारी अब तक पकड़ी नहीं गई है। यह एक बड़ी चुनौती है। इसका हल सिर्फ इतना है कि यदि कोई भी रिस्क फैक्टर खुद में महसूस हो, तो तुरंत टेस्ट कराया जाए। 40 साल की आयु के बाद हर साल आंखों की जांच करानी चाहिए। इस रोग में रेटिना को दिमाग से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त होने लगती है, जिससे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। यह ऑप्टिक नर्व दोबारा नहीं बन पाती।

मधुमेह के 10 में से 6 लोगों को आंखों की समस्या-मधुमेह पीड़ित हर 10 में 6 लोग आंखों से संबंधित रोगों के शिकार हो रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर एडिमा, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा शामिल हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि मधुमेह बढ़ने पर नसों से रक्त रिसाव होने लगता है। आंखों में ब्लड वेसल्स से रिसाव के कारण कई मरीजों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है।

वार्षिक सम्मेलन पर चर्चा के मुद्दे-भविष्य में ऐसा मोबाइल एप लॉन्च होगा, जो एआई की मदद से आंख स्कैन कर ग्लूकोमा पहचान लेगा।

सिंगापुर में रिसर्च चल रही है, जिसमें भारत के विशेषज्ञ ऑप्टिक नर्व को दोबारा बनाने के लिए स्टेम सेल तकनीक पर काम कर रहे हैं।